● वर्ष-6
● अंक-104
रायपुर, गुरुवार
26 नवंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

|| संगछध्वम् संवदध्वम् ||

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-6>> बादलों का घर मेघालय...

सीबीएसई की तीन भाषा नीति पर छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत

दो चुनने वाले दो और तीन चुनने वाले तीन भाषाएं पढ़ेंगे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सीबीएसई की तीन-भाषा नीति के तहत पहले ही तीन भाषाएं चुन चुके छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। उन्हें अब दो भाषाएं चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सीबीएसई की तीन-भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और सीबीएसई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में पेश हुए। न्यायमूर्ति बागची ने कहा, हमने कहा था कि कक्षा 6 के जिन छात्रों ने तीन भाषाएं चुनी हैं, वे तीन भाषाएं जारी रखेंगे। जिन्होंने तीन भाषाएं नहीं चुनी हैं, उन्हें इसके लिए मजबूर न करें, उन्हें उसी तरह पढ़ने दें, जैसे वे अभी पढ़ रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जो छात्र अभी दो भाषाएं पढ़ रहे हैं, उन्हें इस साल दो भाषाएं जारी रखने की अनुमति होगी। यह बच्चों से जुड़ा मामला है। हम इसे यहां नहीं बढ़ाना चाहते। जिन्होंने पहले ही विकल्प चुन लिया है, वे जारी रखें। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जिन छात्रों ने तीन भाषाएं चुनी हैं, उन्हें पुरानी व्यवस्था में लौटने की मांग नहीं करनी चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इस बारे में स्पष्ट करेंगे। जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि छूट दसवीं कक्षा तक देने में दिक्कत हो सकती है, तो न्यायमूर्ति बागची ने कहा, दसवीं तक।



कक्षा 7 के छात्रों को भी आपने यही छूट दी है। इसे देख लीजिए। कक्षा 7 तक के छात्रों को दसवीं तक छूट दी गई है। इस नीति के तहत कम-से-कम दो भाषाएं भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों को इस नियम से छूट मिली है। वे दो विदेशी भाषाएं और एक भारतीय भाषा पढ़ सकते हैं। इन कक्षाओं में तीसरी भाषा की परीक्षा स्कूल में होगी, बोर्ड परीक्षा में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस नीति पर रोक नहीं लगाई थी। हालांकि, अदालत ने अंग्रेजी को गैर-भारतीय मूल की भाषा कहने पर सवाल उठाए थे। उसने सीबीएसई और अन्य अधिकारियों से यह भी पूछा था कि स्कूलों में जरूरी व्यवस्था है या नहीं। सीबीएसई ने अदालत से 28 सितंबर के आदेश में बदलाव करने की मांग की थी। उसका कहना था कि कक्षा 6 से 9 के छात्रों को मिली छूट पर फिर से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ छात्र पहले ही तीन भाषाएं चुन चुके थे। 28 सितंबर के आदेश में अदालत ने सीबीएसई से कहा था कि वह कक्षा 6 के छात्रों को भी कक्षा 7 के छात्रों जैसी छूट देने पर विचार करे।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

एक वकील ने अदालत के पुराने आदेश में कुछ दिक्कत होने की बात कही। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मुझे लगता है कि अब इन मुद्दों को यहीं खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत प्रस्तावित आदेश दे सकती है। अगर कोई दिक्कत हुई, तो सीबीएसई फिर अदालत आएगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम ऐसा करेंगे। बाद में, जब पीठ अगले मामले की सुनवाई शुरू करने वाली थी, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने आदेश में बदलाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सुना नहीं गया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ सिर्फ यह साफ करना चाहती है कि दो भाषाएं पढ़ रहे छात्र दो भाषाएं और तीन भाषाएं चुन चुके छात्र तीन भाषाएं पढ़ते रह सकते हैं। उन्होंने कहा, जिन्होंने तीन भाषाएं चुनी हैं, उन्हें तीन भाषाएं पढ़ने दें। बस इतना ही। गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, यह हर बच्चे का अपना फैसला है। संस्थानों को इस बारे में कोई निर्देश नहीं देना चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्कूलों को अदालत के आदेश का ऐसा मतलब नहीं निकालना चाहिए जिससे तीन भाषाएं चुन चुके छात्रों को दो भाषाओं पर लौटना पड़े।

मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले

20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को मिली मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के विकास को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन बड़े निर्णयों की घोषणा की। इन परियोजनाओं पर कुल 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। कैबिनेट ने कुल पांच प्रमुख योजनाओं को हरी झंडी दी है। इनमें निर्माण और बुनियादी ढांचा उपकरण विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र योजना शामिल है। इसके लिए 11,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। तमिलनाडु के कामराजार पोर्ट पर दूसरा कंटेनर टर्मिनल बनाने का भी निर्णय लिया गया है। इस परियोजना पर 4,288 करोड़ रुपये का व्यय होगा। असम के डोलू, सिलचर में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी गई है। इस हवाई अड्डे के निर्माण पर 2,014 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये परियोजनाएं देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इनसे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। डाक विभाग के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। डाक परिचालन योजना के लिए 1,141 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। वहीं, संपदा प्रबंधन योजना के लिए 1,491 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।



छह यूरिया परियोजनाओं को दी मंजूरी

नई दिल्ली, (ए)। उधर, सरकार ने छह ब्राउनफील्ड गैस-आधारित यूरिया परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 54,000 करोड़ रुपये है। एक न्यूज एजेंसी ने सरकार से जुड़े एक अधिकारी के हवाले से इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी है। यह मंजूरी देश के उर्वरक क्षेत्र में एक बड़ा निवेश दर्शाती है।

उमर-शरजील को अंतरिम जमानत से सुप्रीम इंकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी अंतरिम जमानत की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया।



रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल में आयोजित छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर अवॉर्ड्स 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कंटेंट क्रिएटर्स प्रदेश के डिजिटल ब्रांड एंबेसडर हैं।

100 साल का इंतजार खत्म, ब्रिटेन से नागा पूर्वजों के 39 अवशेष लौटेंगे घर

दीमापुर। नगालैंड के लोगों के लिए 27 नवंबर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। करीब 100 साल पहले नागा समुदाय के 39 पूर्वजों के अवशेष ब्रिटेन ले जाए गए थे। अब ये अवशेष वापस नगालैंड लौट रहे हैं। ये अवशेष ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पिट रिवर्स म्यूजियम में रखे थे। नागा ट्राइब्स होहो (एनटीएच) और फोरम फॉर नागा रिकंसिलिएशन (एफएनआर) ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शनिवार को दीमापुर में इन पूर्वजों के सम्मान में एक खास कार्यक्रम होगा। इसके बाद आम लोग इनके दर्शन कर सकेंगे। लोग वहां श्रद्धांजलि देंगे, फूल चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे। पिट रिवर्स म्यूजियम में नागा समुदाय से जुड़ी चीजों का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। इसका ज्यादातर हिस्सा 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश धिकारियों ने जमा किया था। संग्रहालय के अनुसार, 100 साल से भी पहले जॉन हेनरी हटन ने नागा पूर्वजों के पहले अवशेष इसे दिए थे। हटन अंग्रेजी शासन के समय भारतीय सिविल सेवा में अधिकारी थे। वे मानवविज्ञानी भी थे। बाद में हटन और एक दूसरे अधिकारी जेम्स फिलिप मिल्स ने मिलकर और अवशेष जुटाए। वे दोनों 1910 से 1940 के बीच ज्यादातर अवशेष ऑक्सफोर्ड ले गए थे। इतिहास के दस्तावेजों से पता चलता है कि इनमें से कुछ अवशेष जबरदस्ती लिए गए थे। इन्हें हासिल करने के लिए अंग्रेजी शासन के समय सैन्य हमले भी किए गए थे। इसलिए, इन अवशेषों की वापसी नागा समुदाय के लिए बहुत मायने रखती है। यह सिर्फ पुरानी चीजें वापस लाने की बात नहीं है। यह अपने पूर्वजों को सम्मान देने और इतिहास से जुड़े सवालों के जवाब पाने का मौका है। साल 2020 में संग्रहालय से बातचीत के बाद इन्हें वापस लाने की कोशिश शुरू हुई।



राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है। साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जाए। जिसमें यह भी शामिल है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत कानूनी रूप से विचार योग्य है या नहीं। यह मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास उनकी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में कहीं अधिक संपत्ति है। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को इन आरोपों की जांच करने और उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया था।



विकसित भारत 2047 यात्रा मजबूत सुधारों और निवेश से आकार ले रही

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि विकसित भारत 2047 यात्रा मजबूत सुधारों और मुख्य क्षेत्रों में निवेश से आकार ले रही है। पीएमओ इंडिया ने एक्स पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष आर. मुकुंदन के एक लेख का जिक्र किया। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे बुनियादी ढांचे में निवेश, जीएसटी, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, कॉर्पोरेट कर (टैक्स) में सुधार, पीएलआई योजनाओं और व्यापार समझौतों के जरिये विकास की नींव रखी गई है। पोस्ट में आगे कहा कि भारत की आर्थिक क्षमता को स्थायी समृद्धि में बदलने के लिए सरकार और उद्योग जगत को टीम भारत के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। आर. मुकुंदन ने एक प्रमुख वित्तीय दैनिक समाचार पत्र में एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने कल्पना की है कि अगस्त 2047 में, भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष पर, सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ) के अध्यक्ष क्या लिखेंगे। साथ ही, उन्होंने एक विकसित भारत तक पहुंचने के लिए जरूरी रोडमैप भी पेश किया है।

संविधान दिवस पर आज कांग्रेस का देशव्यापी मार्च

नई दिल्ली। संविधान की रक्षा के लिए चलाए जा रहे अपने अभियान के तहत, कांग्रेस 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर संविधान रक्षा मार्च आयोजित करेगी। यह जानकारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता लखनऊ में एक रैली करेंगे, जो 2027 में होने वाले राज्य चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण संदेश देगी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि हर प्रदेश कांग्रेस समिति (पीसीसी) अपने-अपने राज्य में यह मार्च आयोजित करेगी, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 26 नवंबर को लखनऊ में होने वाले मार्च में शामिल होंगे। हर मार्च की शुरुआत बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर या महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास से होगी, जो संविधान की रक्षा के प्रति कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्र निर्माताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद, कांग्रेस कार्यकर्ता और नागरिक मिलकर संविधान की प्रस्तावना (प्रिएम्बल) पढ़ेंगे। इस दौरान वे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को याद करेंगे।

विरोध से पहले मसौदा तो देखें: सुप्रिया सुले

नई दिल्ली। परिसीमन की कवायद और महिला आरक्षण को लेकर जारी सियासी खींचतान के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने एक संतुलित लेकिन स्पष्ट रुख अपनाया है। उन्होंने विपक्षी दलों और सांसदों से अपील की है कि प्रस्तावित परिसीमन बिल पर किसी भी निष्कर्ष या राय पर पहुंचने से पहले इसका पूरा मसौदा संसद में आने दिया जाए और इसके प्रावधानों का गंभीरता से अध्ययन किया जाए। सुले ने यह भी कहा कि बिना बिल देखे उस पर बहस करना जल्दबाजी है और यह कानून राष्ट्रीय हित में एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। बुधवार को संसद परिसर या मीडिया से बातचीत के दौरान एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले ने परिसीमन प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून की अच्छाई या खामी का आकलन तभी किया जा सकता है, जब उसका पूरा टेक्स्ट और प्रावधान सभी के सामने हों। सुले ने कहा, पहले बिल को पेश होने दीजिए; हमारे पास पूरा बिल आने दीजिए। एक बार जब यह हमारे पास आ जाएगा, तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं—और हो सकता है कि यह एक अच्छा बिल साबित हो।

सुरक्षा बलों ने 40 एकड़ में फैली अवैध अफीम की खेती नष्ट

उखरूल। मणिपुर के उखरुल और कांगपोकपी जिलों में करीब 40 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, उखरुल जिले में सेना की महार रेजिमेंट, आठवीं बिहार रेजिमेंट, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) और राज्य पुलिस के जवानों की संयुक्त टीम ने लिटन थाना क्षेत्र में करीब 20 एकड़ में फैली अफीम की फसल नष्ट कर दी। इस दौरान कथित तौर पर खेती करने वालों द्वारा इस्तेमाल की जा रही तीन झोपड़ियों को भी आग लगा दी गई। एक अन्य अभियान में कांगपोकपी जिला पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), वन विभाग, एनसीबी और सैतु-गामफाजोल के उपमंडल अधिकारियों की संयुक्त टीम ने कौब्रू आरक्षित वन क्षेत्र में के ल्हांगनोम गांव की पहाड़ी श्रृंखलाओं में करीब 20 एकड़ भूमि पर की जा रही अफीम की अवैध खेती को नष्ट कर दिया। पुलिस ने बताया कि अवैध खेती में कथित तौर पर इस्तेमाल की जा रही दो झोपड़ियों को जला दिया गया। इसके अलावा, खरपतवारनाशक और खेती के उपकरण भी नष्ट कर दिए गए। इस संबंध में गामनोम-सापोरमेइना थाने में मामला दर्ज किया गया है।

'द ओडिसी' और 'एवेंजर्स- डूम्सडे' जैसी फिल्मों के साथ मुकाबला

ऑस्कर की रेस में शामिल रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण'

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी फिल्म 'रामायण' इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है। अपने वीएफएक्स को लेकर इसे काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिला है। अब 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स में भी विजुअल इफेक्ट्स श्रेणी में अवॉर्ड के लिए इसने टॉप 20 फिल्मों में अपना स्थान सुरक्षित किया है।

नितेश तिवारी की 'रामायण- राइज ऑफ ए लेजेंड' 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए विजुअल इफेक्ट्स कैटेगरी में टॉप 20 कंटेंडर्स में शामिल हो गई है। 'ड्यून- पार्ट थ्री', 'द ओडिसी' और 'एवेंजर्स- डूम्सडे' जैसे बड़े हॉलीवुड प्रोडक्शन्स के साथ इसका मुकाबला है।

कई सूत्रों ने वैरायटी को बताया कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की विजुअल इफेक्ट्स ब्रांच ने थैंक्सगिविंग हॉलिडे से पहले अगले राउंड में आगे बढ़ने वाली 20 फिल्मों की लिस्ट जारी की है। ये सभी फिल्में अब वोटिंग के अगले राउंड में पहुंच गई हैं। फिल्म रामायण अभी ऑस्कर के फाइनल नॉमिनेशन तक नहीं पहुंची है।

अगर फिल्म आगे चलकर आधिकारिक शॉर्टलिस्ट और फिर नॉमिनेशन तक पहुंचती है तो यह भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। बता दें कि टॉप 20 फिल्मों में शामिल होकर 'रामायण' का मुकाबला हॉलीवुड की कई बड़ी और चर्चित फिल्मों से है।



जिसमें डेनिस विलेन्यूवे की 'ड्यून-पार्ट थ्री', क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी', फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर की 'प्रोजेक्ट हेल मैरी, स्टीवन स्पीलबर्ग की डिस्क्लोजर डे और मार्वल स्टूडियोज की एंथनी और जो रूसो की एवेंजर्स- डूम्सडे शामिल हैं। डिनी चार एंट्रीज के साथ कन्फर्म्ड टाइटल्स में सबसे आगे है। हालांकि, ऑर्गनाइजेशन ने अभी तक लिस्ट का आधिकारिक तौर पर एलान या पुष्टि नहीं की है।

दुनियाभर में बजा रामायण का डंका- बता दें कि फिल्म रामायण 05 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसने नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है। भारत में यह 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है।

वहीं, वर्ल्डवाइड यह 1700 करोड़ से यादा का कलेक्शन जुटा चुकी है। बता दें कि इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं। साई पल्लवी सीता के रोल में हैं। यश ने रावण के रोल निभाया है।

आरआरआर भी हुई थी टॉप 20 में शामिल- रामायण से पहले साल 2023 में एसएस राजामौली की आरआरआर फिल्म भी 95वें एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए विजुअल इफेक्ट्स कैटेगरी में टॉप 20 कंटेंडर्स में शामिल थी। हालांकि, यह फाइनल नॉमिनेशन में जगह नहीं बना पाई थी। राम चरण और जूनियर ह्वज़क्र की इस पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म ने नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीता। इससे यह अवॉर्ड जीतने वाला पहला इंडियन गाना बन गया।

कब होगा ऑस्कर अवॉर्ड्स का आयोजन?- ऑस्कर शॉर्टलिस्ट के लिए वोटिंग 7 दिसंबर से शुरू होगी और 11 दिसंबर को खत्म होगी। सभी कैटेगरी की शॉर्टलिस्ट का एलान 15 दिसंबर को होगा। फाइनल नॉमिनेशन 21 जनवरी को अनाउंस किए जाएंगे। 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स 14 मार्च को ओवेशन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में होंगे।

एनएमडीसी की खनन व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

कांग्रेस ने प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया आरोप

जगदलपुर। बस्तर में खनन के नाम पर आखिर किस कीमत पर विकास किया जा रहा है? क्या उद्योगों के मुनाफे के आगे पर्यावरण और ग्रामीणों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है? दंतेवाड़ा में एनएमडीसी के खनन क्षेत्र में टेलिंग्स का पहाड़ खिसकने से हुई तबाही के बाद अब ये सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। हादसे के सात दिन बाद कांग्रेस का सात सदस्यीय जांच दल घटना स्थल पहुंचा। जांच दल ने मौके के हालात का जायजा लेने के बाद इस पूरी घटना के लिए एनएमडीसी प्रबंधन की कथित लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया।कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही की सजा आज आसपास के ग्रामीणों और प्रकृति को भुगतनी पड़ रही है। पार्टी ने हादसे की उच्चस्तरीय जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई और प्रभावित क्षेत्र के पर्यावरणीय नुकसान का विस्तृत आकलन कराने की मांग की है।दरअसल घटना स्थल के निरीक्षण से पहले ही एनएमडीसी प्रबंधन और कांग्रेस नेताओं के बीच सर्किट हाउस में तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस का सात सदस्यीय जांच दल जब घटना स्थल जाने की तैयारी कर रहा था, तब प्रबंधन की ओर से केवल सात



गाड़ियों को जाने की अनुमति देने की बात कही गई। इस पर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताई। नेताओं ने सवाल उठाया कि जब जांच का उद्देश्य हादसे की वास्तविक स्थिति और नुकसान का आकलन करना है तो जांच दल की आवाजाही पर इस तरह की पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? कांग्रेस नेताओं ने इसे जांच प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप बताते हुए विरोध दर्ज कराया। हालांकि, बाद में प्रबंधन ने सभी गाड़ियों को घटना स्थल तक जाने की अनुमति दे दी।उपनेता प्रतिपक्ष एवं बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल की अध्यक्षता में जांच दल मौके पर पहुंचा और टेलिंग्स के मलबे से प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया। घटना स्थल से लौटने के बाद विधायक लखेश्वर बघेल ने जो तस्वीर सामने रखी, उसने हादसे की गंभीरता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। उनके मुताबिक टेलिंग्स का विशाल पहाड़ खिसकने से चार प्राकृतिक नाले पूरी तरह दब गए हैं। लाखों पेड़ों के बर्बाद होने और हजारों जीव-जंतुओं के मलबे में जमींदोज होने का दावा भी उन्होंने किया।बघेल ने कहा कि यह केवल लोहागांव तक पहुंचने का रास्ता बंद होने की घटना नहीं है, बल्कि आयरन हिल के नीचे बसे तमाम गांवों के लिए गंभीर संकट है। प्राकृतिक जलस्रोतों, जंगलों और वन्यजीवों को हुए नुकसान का असर आने वाले लंबे समय तक दिखाई दे सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर खनन क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था कितनी मजबूत थी, जिसके बावजूद टेलिंग्स का इतना बड़ा पहाड़ खिसक गया? कांग्रेस का आरोप है कि ह्रस्ष्टष्ट प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा अब स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस जांच दल ने इस पूरे मामले में एनएमडीसी प्रबंधन की जवाबदेही तय करने की मांग की है। नेताओं का कहना है कि हादसे के वास्तविक कारणों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यह भी सामने आना चाहिए कि टेलिंग्स के भंडारण, रखरखाव और सुरक्षा के लिए निर्धारित मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं।

कार्तिक पूर्णिमा पर खैरागढ़ में काशी हरिद्वार जैसा नजारा



खैरागढ़-एमसीबी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर घाटों पर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ विशेष महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती में श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव के साथ सहभागिता निभाई शंखनाद, घंटियों की गूंज और भगवान के जयकारों से पूरा नदी तट भक्तिमय हो उठा। खैरागढ़ में गंगेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में हरिद्वार और काशी की तर्ज पर तीसरे वर्ष भी भव्य गंगा आरती एवं दीपदान का आयोजन किया गया। दीपों की जगमगाहट और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरा घाट भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो उठा। शाम 7 बजे दीपदान और नगर के प्रतिष्ठित म्यूजिकल ग्रुप %कलाकारों की दुनिया% के सुमधुर भजनों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कलाकारों की सुरीली प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को भक्तिरस में डुबो दिया। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ गंगा आरती शुरू हुई।

सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद रही। विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने गंगा आरती की। इस अवसर पर पूर्व विधायक खुज्जी छत्री साहू, आरती रिंकू महोबिया, विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन, नेता प्रतिपक्ष दीपक देवांगन, अय्यूब सोलंकी, चंद्रशेखर यादव, गंगेश्वर मंदिर समिति के सुरेश ठाकुर, डॉ। अरुण भारद्वाज, केसर सेन, मनोहर सेन सहित बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे।विधायक यशोदा वर्मा ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा आरती करना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। गंगा हमारी मां हैं और उसे स्वच्छ रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। नदियों में गंदगी नहीं डालनी चाहिए। नगर और नदियों को स्वच्छ रखना केवल जनप्रतिनिधियों की नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।कई लोग हरिद्वार काशी प्रयागराज नहीं पहुंच पाते, ऐसे लोग कार्यक्रम में पहुंचकर बहुत उत्साहित नजर आए-डॉ। अरुण भारद्वाज, आयोजन समिति के सदस्यगंगा आरती में शामिल होने वाले सभी नगरवासियों और श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष इस आयोजन को और अधिक भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की व्यवस्था भी की गई। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मनेन्द्रगढ़ में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। धार्मिक आस्था के इस विशेष पर्व पर हसदेव गंगा तट सहित शहर के विभिन्न नदी एवं जलाशय घाटों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने जल में स्नान कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की तथा परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की।

ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे 13 खिलाड़ियों की मोबाईल पार



दुर्ग। भिलाई के सिविक सेंटर स्थित भिलाई निवास के सामने साइकिल पोलो ग्राउंड में अभ्यास करने पहुंचे खिलाड़ियों के साथ चोरी की घटना हो गई। खिलाड़ियों के 13 मोबाइल फोन एक ही स्कूटी की डिक्की से गायब हो गए। सभी खिलाड़ी अभ्यास में व्यस्त थे। जब अभ्यास खत्म होने के बाद उन्होंने स्कूटी की डिक्की खोली तो उसमें रखे मोबाइल नहीं मिले। घटना के बाद खिलाड़ियों ने भिलाई नगर थाना कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मिली जानकारी के मुताबिक, जयंती स्टेडियम बंद होने के कारण खिलाड़ी इन दिनों भिलाई निवास ग्राउंड में अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास के दौरान सभी ने अपने मोबाइल फोन सुरक्षित रखने के लिए एक स्कूटी की डिक्की में रख दिए थे। इस तरह कुल 13 मोबाइल एक ही जगह रखे हुए थे। खिलाड़ियों को उम्मीद थी कि अभ्यास पूरा होने तक उनके फोन सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वापस लौटने पर डिक्की खाली मिली। चोरी हुए सभी 13 मोबाइल एण्ड्रॉईड और बजट श्रेणी के बताए जा रहे हैं। खिलाड़ियों के मुताबिक, ये महंगे फोन नहीं थे, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े थे। मोबाइल चोरी होने से खिलाड़ियों को आर्थिक नुकसान के साथ पढ़ाई और दूसरे जरूरी कामों में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल में मौजूद शैक्षणिक दस्तावेज और दूसरी जरूरी जानकारियों के कारण उनकी परेशानी और बढ़ गई है। अभ्यास के दौरान खिलाड़ियों के साथ भिलाई विद्यालय सेक्टर-2 के रिटायर्ड शिक्षक आर. सुनील कुमार भी मौजूद थे। वे बच्चों को नि:शुल्क एथलेटिक्स ट्रेनिंग देते हैं। घटना के बाद खिलाड़ियों और कोच ने मिलकर पुलिस से शिकायत की और चोरी हुए मोबाइल जल्द बरामद करने की मांग की है। खिलाड़ियों ने पुलिस और क्राइम ब्रांच से मामले की गंभीरता से जांच करने की अपील की है। उनका कहना है कि ये मोबाइल केवल फोन नहीं थे, बल्कि पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और खेल से जुड़ी तैयारियों के लिए जरूरी दस्तावेजों और जानकारियों का जरिया भी थे।

छात्रावास छात्रों ने अधीक्षिका बदलने की मांग की

दाल के नाम पर पानी परोसने का आरोप



जगदलपुर। स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी शिक्षक और प्रशासन की होती है, लेकिन जब छात्राओं को हॉस्टल में भरपेट भोजन तक न मिले तो उनकी पढ़ाई और सेहत दोनों पर सवाल खड़े होना लाजिमी है। बस्तर जिले के खंड शिक्षा परियोजना भानपुरी के अंतर्गत बेसौली स्थित छात्रावास की छात्राएं अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचीं। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जा रहा। दाल के नाम पर सिर्फ पानी परोसा जाता है। इतना ही नहीं, आवश्यक सामग्रियों में कटौती और अधीक्षिका के व्यवहार को लेकर भी छात्राओं ने गंभीर शिकायतें की हैं। छात्राओं ने अधीक्षिका सुलोचना दीवान को हटाकर नई अधीक्षिका नियुक्त करने की मांग की है।दरअसल कलेक्ट्रेट परिसर में स्कूल की ड्रेस पहने पहुंची ये बच्चियां किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में शामिल होने नहीं बल्कि अपने हक की आवाज उठाने आई थीं। इनके हाथों में शिकायत का आवेदन था और उस आवेदन में दर्ज थीं छात्रावास की ऐसी परेशानियां, जो सीधे बच्चियों की सेहत सुरक्षा और पढ़ाई से जुड़ी हैं। छात्राओं ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि सितंबर 2026 से पदस्थ अधीक्षिका सुलोचना दीवान के आने के बाद से छात्रावास की व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। छात्राओं का कहना है कि उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, दाल के नाम पर केवल पानी परोसा जाता है और जरूरी सामग्री में भी कटौती की जा रही है। छात्राओं ने यह भी शिकायत की है कि अधीक्षिका भानपुरी से आना-जाना करती हैं और छात्रावास में नहीं रुकतीं। उनके मुताबिक अधीक्षिका केवल एक से डेढ़ घंटे के लिए आती हैं और शिकायत करने पर चिड़चिड़ा व्यवहार करती हैं। बच्चियों के बीमार होने पर भी समुचित व्यवस्था करने के बजाय पालकों को बुलाने की बात कही जाती है। छात्राओं ने यह भी बताया कि दीपावली के बाद से अब तक अधीक्षिका छुट्टी से वापस नहीं लौटी हैं। हालांकि बच्चियों ने कैमरे पर अपनी बात रखने से इनकार कर दिया, लेकिन स्कूल ड्रेस में सामूहिक रूप से कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने लिखित शिकायत के जरिए अपनी परेशानी प्रशासन तक पहुंचाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रावास में मिलने वाले भोजन और जरूरी सुविधाओं में आखिर कटौती क्यों हो रही है? क्या प्रशासन की निगरानी में कमी है या फिर छात्राओं के हिस्से के भोजन में कहीं सेंध लग रही है? इन आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक थाली में परोसी जा रही दाल का नहीं है। सवाल उन बच्चियों के पोषण, स्वास्थ्य और भविष्य का है, जो बेहतर शिक्षा की उम्मीद में छात्रावास में रह रही हैं। जब पेट ही नहीं भरेगा तो बच्चियां पढ़ाई पर ध्यान कैसे देंगी?

जेन-जी भी बाबा के झांसे में :रूहानी ताकतों का मालिक होने का दावा



अंबिकापुर। 21वीं सदी में भारत,ढ्ढ जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगने का खेल जारी है। कई ग्रामीण इलाकों में भोले-भाले लोग फर्जी बाबाओं के झांसे में आ जाते हैं। इस चक्कर में वह लाखों रुपये न्योछावर कर देते हैं। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से सामने आया है। जहां खुद को रूहानी ताकतों का मालिक बताने वाले एक कथित बाबा पर ठगी और आस्था से खिलवाड़ करने के आरोप लगे हैं। बाबा के झांसे में कई त्नद्दर्ठ्ठ भी आ चुके हैं। लगभग 1 साल से चल रहे कथित पाखंड के खेल का मामला अब थाना पहुंच गया है। आस्था से खिलवाड़ और ठगी के आरोप लगाकर लोगों ने पुलिस से बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला कोतवाली थाना का है। जानकारी के मुताबिक, रसूलपुर में रकह बाबे शिफा के नाम अपना ठिकाना बना रखा था। जहां वह मुस्लिम समुदाय के लोगों को रूहानी ताकतों का मालिक बताता और बिमारी ठीक करने का झांसा देता था। उसपर बैकुंठपुर के एक व्यक्ति समेत अन्य लोगों से भी लाखो रुपये की ठगी का आरोप लगा है। मोहल्लेवासियों ने आरोप लगाया है कि उनके मोहल्ले में निवास कर रहे फर्जी बाबा ने खुद को उत्तर प्रदेश के जोनपुर निवासी होना बताया है। फर्जी बाबा के द्वारा धर्म के नाम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को कई तरह का झांसा देकर चूना लगाया गया है। वह दावा करता है कि वह रूहानी ताकतों का मालिक है। बेऔलादों को औलाद दे सकता है। किसी भी बीमारी का इलाज तंत्र मंत्र से कर सकता है। उसने कई लोगों से फोन पे के माध्यम से डेढ़ लाख रूप से अधिक की ठगी की है। स्थानीय निवासी अनीश वारसी ने बताया कि बाबा दावा करता है कि जिनका बच्चा उन्हें बच्चा करा सकते है। नौकरी लगवा सकते है। मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकते है। कई चमत्कार के दावे किए जाते हैं, लेकिन पैसे लेने के बाद कुछ चमत्कार जैसा नहीं होता है। इसका फोकस त्नद्दर्ठ्ठ पर है। हाल में एक व्यक्ति के बच्चे की तबीयत ठीक करने के नाम पर लगभग 4.5 लाख रुपये लिए, लेकिन 2 महीने बाद उसकी मौत हो गई। जवाबदेही पर वह कहता है कि मेरे पास जिन्नात है और तुम लोगों का घर खराब कर दूंगा। आक्रोशित मोहल्लेवासियों ने बाबा के खिलाफ थाना पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी को शिकायत देकर बाबा के खिलाफ स्नढ्ढक्रदर्ज करने की मांग की। शिकायत में उन्होंने बाबा को दिए ऑनलाइन पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स की फोटोकॉपी भी संलग्न भी किए हैं। मामले में पुलिस की जांच को लेकर पूरी स्थिति साफ हो पाएगी।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बालोद में म्यूजिक टीचर छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार

बालोद। दल्लीराजहरा में एक म्यूजिक टीचर ने अपनी ही 11 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। घटना दल्लीराजहरा नगर में संचालित एक निजी स्कूल की है। यहां संगीत सिखाने वाले शिक्षक ने 11 वर्षीय मासूम छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हुए बैड टच की घिनौनी हरकत की। घर पहुंचने के बाद डरी-सहमी बच्ची ने हिम्मत जुटाकर माता पिता को घटना के बारे में बताया। वे तत्काल दल्लीराजहरा थाने पहुंचे और आरोपी टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। नाबालिग से जुड़े इस संवेदनशील मामले में पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी राजहरा विनोद मंडावी ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर दल्लीराजहरा थाने में आरोपी शिक्षक के विरुद्ध पॉक्सो) एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

उच्चाधिकारियों को सूचना दिए बगैर जुए के फड़ में मारी रेड

सक्ती। उच्च अधिकारियों को सूचना दिए बगैर जुए के फड़ पर छापा मारना प्रशिक्षु उप निरीक्षक के लिए भारी पड़ गया। फड़ में शामिल एक शख्स की भागते समय तालाब में कूदने से हुई मौत के बाद कार्रवाई करते हुए एसपी ने प्रशिक्षु एसआई को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए डभरा एसडीओपी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।बता दें कि जुआ खेले जाने की सूचना पर रविवार देर रात हसौद पुलिस ने गांव में दबिश दी थी। पुलिस को देख जुआ खेल रहे गांव के ही महेश राम केंवट ने तालाब में छलांग लगा दी, जिसके बाद से वह लापता हो गया था। आज सुबह तालाब उसका शव तैरता मिला। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्ट के लिए भेज दिया है।युवक की मौत से आक्रोशित परिजन पुलिस ने मृतक के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ प्रशासन से एक करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग करते हुए चक्काजाम कर दिया है। मामले में बिना सूचना के छापा मारने पर सक्ती एसपी ने कार्रवाई करते हुए हसौद थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप निरीक्षक जयराम साहू को निलंबित किया है।

2.20 करोड़ के साइबर फ्रॉड मामले में तीन आरोपियों जमानत रद्द

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक से जुड़े 2.20 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में आरोपी अभिलाष कुमार डेनियल, आशीष तिवारी और नरेंद्र कुर्रे की जमानत याचिकाएं खारिज कर दिया गया है। अब तीनों आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। मामले के अनुसार, मई और जून 2026 के बीच बैंक खाते में करीब 2.20 करोड़ रुपये जमा किए गए और इसके बाद अलग-अलग माध्यमों से रकम निकाल ली गई। आरोप है कि साइबर ठगी की रकम के लेन-देन के लिए आरोपियों ने अपने बैंक खाते उपलब्ध कराए थे। इसके बदले प्रत्येक आरोपी को 20-20 हजार रुपये कमीशन दिया गया था। मामले में आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। इस फैसले से आरोपियों को राहत नहीं मिल सकी है।

केन्द्र प्रबंधक की अनुपस्थिति में धान खरीदी ठप

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। खोडरी धान खरीदी केंद्र में लापरवाही और वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण धान खरीदी का कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गया है। केंद्र प्रबंधक की अनुपस्थिति में किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को प्रभार नहीं सौंपा गया है। ऐसे में केंद्र के कर्मचारी धान की खरीदी करने से हिचकिचा रहे हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार, वर्तमान में 13 किसान अपनी उपज बेचने के लिए ट्रैक्टरों में धान लोड कर खरीदी केंद्र के बाहर खड़े हैं। सुबह से इंतजार करने के बावजूद तौल शुरू न होने से किसानों को मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि यदि प्रबंधक अवकाश पर हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इस संबंध में खोडरी धान खरीदी केंद्र के नोडल अधिकारी ने बताया कि प्रबंधक नवीन साहू संभवत: मेडिकल लीव पर हैं। उनका प्रभाव किसी को भी प्रभार नहीं दिया जा सका है।

महिला व्याख्याता का संतान पालन अवकाश एचसी से मिली स्वीकृत

बिलासपुर।एचसी के दखल के बाद शासकीय स्कूल में पदस्थ महिला व्याख्याता राजश्री कौशिक का जिला शिक्षा अधिकारी ने संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और ऋषभदेव साहू ने पैरवी की। जानकारी के अनुसार, सेजेस शासकीय कन्या विद्यालय, बिलासपुर में व्याख्याता के पद पर पदस्थ राजश्री कौशिक के पैर में जुलाई 2026 में चोट लग जाने से उनका लिगामेंट डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से वह अपने पांच वर्षीय पुत्र की उचित तरीके से देखभाल नहीं कर पाने के कारण बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष संतान पालन अवकाश दिए जाने की मांग की थी। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी नहीं दी। इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं ऋषभदेव ने यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के नियम के तहत शासकीय महिला अधिकारी / कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान कुल 730 दिवस संतान पालन अवकाश की पात्र है।

स्त्री स्किल सेंटर: दुनिया के कोने-कोने में पहुंचेगा अब धमतरी का सामान



धमतरी। छत्तीसगढ़ की महिलाएं अब अपने हुनर को सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रखेंगी, बल्कि उनके हाथों से तैयार किए गए उत्पाद विदेशी बाजारों तक अपनी पहुंच बनाएंगे। जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके पारंपरिक हुनर को ग्लोबल मार्केट पर पहचान दिलाने के लिए बड़ा प्रयास शुरू किया गा है, जिसका नाम है स्त्री स्किल सेंटर।

एनआईटी रायपुर और धमतरी प्रशासन के संयुक्त प्रयास से भोपाल राव पवार शासकीय पॉलिटेक्निक में देश का पहला %स्त्री% स्किल सेंटर शुरू हो चुका है। यहां महिलाओं को हथकरघा और टेक्सटाइल उत्पादों के निर्माण से लेकर उनकी मार्केटिंग और कारोबार शुरू करने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना में जो सबसे खास बात यह है कि यहां महिलाओं को ही केवल प्रशिक्षण ही नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें अपना ब्रांड और स्टार्टअप खड़ा करने में हर संभव मदद भी दी जाएगी।

स्त्री स्किल सेंटर शुरू होने से धमतरी के पारंपरिक खादी और सूत कातने और बनाने के हुनर को अब अंतरराष्ट्रीय बाजार तक न सिर्फ पहचान मिलेगी बल्कि उसे वहां तक पहुंचाया भी जाएगी। स्त्री स्किल सेंटर उन माताओं और बहनों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने जा रहा है, जो अपने पारंपरिक हुनर को रोजगार और व्यवसाय में बदलना चाहते थे। एनआईटी रायपुर और धमतरी जिला प्रशासन ने मिलकर इस केंद्र की शुरुआत की है। यहां महिलाओं को हथकरघा वस्त्रों के निर्माण, डिजाइन, उत्पादन और मार्केटिंग से जुड़ी बारीकियां सिखाई जाएंगी। इसके साथ ही महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने और अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए भी मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया जाएगा।

धमतरी जिला प्रशासन के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को केवल हुनरमंद बनाना नहीं, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर उद्यमी के रूप में पहचान दिलाना भी है।

महिलाएं अपने तैयार उत्पादों का खुद का ब्रांड विकसित कर सकें और उन्हें देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचा सकें, इसी दिशा में सेंटर काम करेगा। छत्तीसगढ़ के खादी और सूत से बने उत्पादों की मांग को देखते हुए इस क्षेत्र में रोजगार और कारोबार की अच्छी संभावनाएं हैं। इसी सोच के साथ इस पहल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, ताकि स्थानीय संसाधनों और महिलाओं के हुनर को बड़े बाजार से जोड़ा जा सके-डॉ। अनुज शुक्ला, प्रोफेसर, एनआईटी, रायपुर हम कह सकते हैं कि धमतरी में शुरू हुआ यह स्त्री स्किल सेंटर महिलाओं के हुनर को कारोबार में बदलने का एक नया मंच बन सकता है। अब देखना होगा कि यहां से प्रशिक्षण लेकर निकलने वाली महिलाएं अपने उत्पादों के जरिए छत्तीसगढ़ की पहचान देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक किस तरह पहुंचाती हैं।

पासिंग आउट परेड में नवआरक्षकों ने दिखाया दमखम



राजनांदगाँव। राजनांदगांव के पीटीएस ग्राउंड में अनुशासन और कदमताल का नजारा दिखा, जब 84वें सत्र के नवआरक्षकों ने पासिंग आउट परेड में अपना दमखम दिखाया। बस्तर से लेकर रायपुर और अन्य जिलों से आए 678 नवआरक्षकों ने महीनों की कड़ी मेहनत और आउटडोर-इनडोर ट्रेनिंग के बाद वर्दी की जिम्मेदारी संभाली है।

समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नवआरक्षकों को मंच से सम्मानित भी किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, यह अब तक का सबसे बड़ा कॉन्स्टेबल बैच है, जिसे वीआईपी और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के व्यावहारिक अनुभव के साथ तैयार किया गया है। 14 जनवरी से शुरू हुए इस प्रशिक्षण सत्र में 472 पुरुष और 206 महिला आरक्षक अब विभिन्न जिलों और थानों में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। इस बैच में फ्रेश रिक्रूट्स के साथ-साथ आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल रहे, जिन्हें पारंपरिक ड्रिल व फील्ड क्राफ्ट के साथ आधुनिक पुलिसिंग, साइबर, फॉरेंसिक, एनडीपीएस और कानून-व्यवस्था से जुड़ी बारीकियों का प्रशिक्षण दिया गया है। कठिन प्रशिक्षण और चुनौतियों के बीच खरा उतरने के बाद नवआरक्षकों के चेहरों पर नई शुरुआत की खुशी साफ दिखी। बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटी वनीता सोरी जैसी नवआरक्षकों के लिए यह वर्दी गर्व और नए अवसर का प्रतीक बनी है, वहीं बलौदाबाजार की उजाला कामरी सहित अन्य जवानों ने कठिन मेहनत के बाद परेड पूरी होने पर संतोष जताया।

संक्षिप्त समाचार

शराब घोटाला का फरार आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू दुबई में पकड़ाया



रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आई है। फरार आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू (शिब्बू) को दुबई में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उसे अब युनाईटेड अरब अमीरात (यूएई) से भारत लाने की तैयारी चल रही है। शराब घोटाले का मुख्य आरोपी विकास अग्रवाल साल 2023 से फरार चल रहा था, जिसके हफ्तेभर पहले दुबई में गिरफ्तारी हुई थी, चूंकि दुबई में यूएई का कानून लागू होता है, जिसकी वजह से यूएई सरकार फरार विकास अग्रवाल को भारत भेज रही है, जिसे लाने के लिए एसीबी/ईओडब्ल्यू चीफ अमरेश मिश्रा समेत विशेष टीम जल्द यूएई रवाना होगी। टीम के विदेश असाइनमेंट से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज तैयार हो चुके हैं। बता दें कि विकास अग्रवाल पर डिस्टिलरी और एफएल -10 ए लाइसेंस धारकों से कमीशन वसूली का आरोप है। विकास अग्रवाल अनवर ढेबर तक अवैध फंड पहुंचाने की मुख्य कड़ी माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विकास को भारत में लाए जाने के बाद एसीबी/ईओडब्ल्यू की पूछताछ में अवैध पैसों के लेन-देन और अंतिम लाभार्थियों के बड़े राज खुलेंगे।

समय-सीमा में चावल जमा नहीं करने पर 34 राइस मिलों को कारण बताओ नोटिस



रायपुर। बस्तर जिले के लिए तय समय-सीमा में चावल जमा नहीं करने पर रायपुर जिले की 34 राइस मिलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद आरंग क्षेत्र के मंदिर हसौद स्थित कमल राइस मिल की जांच की गई। अनियमितता मिलने और निर्धारित समय में चावल जमा नहीं करने की पुष्टि के बाद प्रशासन ने मिल को सील कर दिया। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक रायपुर जिले की मिलों पर बस्तर के लिए कुल 66,207.19 क्विंटल चावल जमा करना बाकी है। इसमें 11,221.68 क्विंटल स्टेट पूल और 54,985.52 क्विंटल सेंट्रल पूल का चावल शामिल है। विभागीय सूची में कमल राइस मिल के नाम पर कुल 5,526.90 क्विंटल चावल जमा करना बाकी दर्ज है। इसमें 4,783.11 क्विंटल स्टेट पूल और 743.79 क्विंटल सेंट्रल पूल का चावल शामिल है। प्रशासन ने 24 नवंबर को मिल की जांच के बाद उसे सील कर दिया।

खेत से बोर पंप और केबल वायर चोरी करने वाले नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार



रायपुर। कुरा में किसानों के खेतों से बोर पंप मशीन और केबल वायर चोरी करने के मामले में धरसींवा पुलिस ने एक युवक के साथ उसके दो नाबालिग साथियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने चोरी की बोर पंप मशीन को छिपाकर रखा था, जबकि केबल वायर को जलाकर उसमें से तांबा निकाल लिया और बेच दिया था। धरसींवा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुरा निवासी शकुंतला धीवर ने 23 नवंबर को चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर की रात कुरा श्मशान घाट के पास स्थित पटेल बाड़ी से मोटर पंप मशीन और केबल वायर चोरी हो गए थे। शिकायत पर धरसींवा थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुरा के दर्री तालाब के पास अमन धीवर (19) चोरी की बोर पंप मशीन बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने अपने दो साथियों नीरज धीवर और पुष्पेंद्र साहू के साथ मिलकर चोरी करना कबूल किया। मामले में अमन धीवर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दोनों नाबालिगों को भी गिरफ्तार कर बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है।

नृपेंद्र मिश्र से राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने नई दिल्ली में की सौजन्य भेंट

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर गणेश शंकर मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में संचालित प्रमुख विकास योजनाओं एवं नीतिगत पहलों की जानकारी दी। मिश्रा ने विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों तथा प्रदेश के समग्र, समावेशी एवं सतत विकास के लिए उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों से मिश्र को अवगत कराया।

श्री श्याम महोत्सव का श्याम बाबा को दिया गया प्रथम निमंत्रण

रायपुर। राजधानी रायपुर में श्री श्याम परिवार सेवा समिति की ओर से आयोजित श्री श्याम प्रभु खाटू वाले का श्री श्याम महोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। इस साल का आयोजन अग्रेसन धाम, छोकरानाला में और भी बड़े स्वरुप में शनिवार 19 दिसंबर 2026 को किया गया है। श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने से पहले श्याम महोत्सव का प्रथम निमंत्रण पत्रिका श्याम मंदिर समता कालोनी में श्याम बाबा के श्रीचरणों में अर्पित करते हुए आयोजन की सफलता के लिए आर्शिवाद मांगा गया।

पीएम जनमन योजना के तहत जशपुर को पांच बड़े पुलों की सौगात

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय क्षेत्रों में मजबूत हो रही सड़क



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के दूरस्थ एवं जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सड़क संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत जशपुर जिले को पांच वृहद पुलों के निर्माण की सौगात मिली है। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इन पुलों के निर्माण के लिए कुल 16 करोड़ 3 लाख 34 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के बैच-। में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 6 नवंबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में 167 पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के पांच वृहद पुल शामिल हैं। इन पुलों के निर्माण से विशेष रूप से दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी तथा ग्रामीण बसाहटों का मुख्य मार्गों से संपर्क मजबूत होगा।

स्वीकृत कार्यों के तहत डंगरी से दरावाकोना मार्ग पर नाले में 60 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 3 करोड़ 56 लाख 23 हजार रुपये तथा जबला से नवापारा मार्ग पर नाले में 30 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 1 करोड़ 83 लाख 21 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार कमरीमा मंझाटोली से खपरीडीह मार्ग पर नाले में 60 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 4 करोड़ 4 लाख 19 हजार रुपये, बगीचा-कांसाबेल मार्ग से जनकपुर पहुंच मार्ग पर नाले में 80 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 3 करोड़ 52 लाख 67 हजार रुपये तथा कुहापानी से बांसधार मार्ग पर नाले में 60 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 3 करोड़ 7 लाख 4 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

इन पुलों के निर्माण से वर्षा ऋतु में नालों के कारण आवागमन बाधित होने की समस्या से ग्रामीणों को राहत मिलेगी। किसानों को अपनी कृषि उपज बाजार तक पहुंचाने, विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों तक जाने तथा मरीजों को समय पर स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। इसके साथ ही स्थानीय व्यापार, रोजगार एवं आजीविका संबंधी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। बेहतर सड़क संपर्क से दूरस्थ जनजातीय बसाहटों तक शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और आवश्यक सेवाओं की पहुंच भी आसान होगी। इन पुलों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। सभी स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित राशि के अंतर्गत पूर्ण किए जाएंगे। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।

गुजरात के नन्द घरों का अवलोकन करने पहुंचीं मंत्री राजवाड़े

■ **गुजरात की महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. मनीषा राजीवभाई वकील से की सौजन्य मुलाकात**

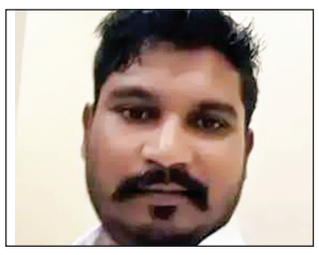


रायपुर। हर बच्चे को पोषण, सीखने और सुरक्षित बचपन का अवसर मिले इसी संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने गुजरात प्रवास के दौरान गांधीनगर यूनिट 2 के ग्राम करई में नन्द घरों (आंगनबाड़ी) का भ्रमण किया। आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्होंने बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को देखा और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।नक्शे देखें

बच्चों की खिलखिलाहट, सीखने की जिज्ञासा और उनके बेहतर भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने केंद्रों की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। नन्द घर केवल सेवा केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के शुरुआती जीवन को संबल देने और माताओं तक जरूरी सहयोग पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। यहां मिलने वाली देखभाल और सीखने का वातावरण बच्चों के आत्मविश्वास और विकास की नींव मजबूत करता है। गांधीनगर स्थित सचिवालय में मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने गुजरात की महिला एवं बाल विकास (महिला एवं बाल कल्याण) मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. मनीषा राजीवभाई वकील से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सामरी की विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा,गुजरात के महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री राकेश शंकर और छत्तीसगढ़ की विभागीय संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। इस दौरान विभागीय योजनाओं, आंगनबाड़ी सेवाओं और महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। मंत्री ने गुजरात में अपनाई जा रही व्यवस्थाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली।

यह दौरा राज्यों के बीच अनुभव साझा करने और बच्चों तथा महिलाओं के लिए चल रही सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण रहा। गुजरात के नन्द घरों में देखे गए प्रयास छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों को और बेहतर बनाने तथा हर बच्चे तक पोषण, शिक्षा और संवेदनशील देखभाल पहुंचाने के संकल्प को नई दिशा दे सकते हैं।

कारोबारी को धमकाने वाले कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज



रायपुर। 22 नवंबर को कारोबारी विजय जेठानी के पास एक अज्ञात नंबर से दोपहर 12:56 बजे फोन आया और फोन करने वाले ने खुद को उमेश रगड़े बताया और गोलू रगड़े व अतुल तलमेल के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया। कारोबारी ने मना किया तो उन्हें गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकी दी गई। क्योंकि कारोबारी ने 21 नवंबर को गोलू रगड़े उर्फ शंका और अतुल तलमेल के खिलाफ आजाद चौक थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कारोबारी विजय जेठानी ने 24 नवंबर को आजाद चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(4) के तहत अपराध दर्ज किया है। शिकायत में फोन करने वाले की पहचान अज्ञात मोबाइल नंबर के धारक के रूप में दर्ज है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कॉल करने वाले ने अपनी पहचान उमेश रगड़े के रूप में बताई थी। उमेश रगड़े कांग्रेस के एससी-एसटी सेल का नेशनल कोऑर्डिनेटर और यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बताया जा रहा है। वहीं मारपीट के मामले में आरोपी अतुल तलमेल जेल में बंद है। गोलू रगड़े और उमेश रगड़े फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस तमाम आरोपों और वायरल ऑडियो की जांच कर रही है।

पेंड्रावन जलाशय विवाद : भूपेश बघेल की सरकार को दो टूक, कहा-

वापस लें अनुमति, नहीं तो कांग्रेस करेगी आंदोलन



रायपुर। छत्तीसगढ़ में पेंड्रावन-बंगोली जलाशय में खनन को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को एक्टिविस्ट आलोक शुक्ला के साथ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने सरकार को दो टूक चेतावनी दी है कि सरकार लीज अनुमति वापस नहीं लेती है, तो कांग्रेस आंदोलन करेगी।

कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पेंड्रावन जलाशय क्षेत्र में खनन की अनुमति न कांग्रेस सरकार और न रमन सिंह सरकार ने दिए, लेकिन वर्तमान सरकार ने खदान को लीज पर दे दिया। यह सरकार का किसान विरोधी रवैया है।

उन्होंने कहा कि पेंड्रावन जलाशय क्षेत्र को लेकर जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में जलाशय और बांध को नुकसान होने की बात कही गई थी। स्थानीय ग्रामीण ने भी लीज रद्द करने की मांग की। सरकार अगर यह लीज वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस इसे लेकर किसानों के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। वहीं विधानसभा में इस मामले को उठाया जाएगा।

मौसम की मार और धान खरीदी में किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर भी भूपेश बघेल ने साय सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों चक्रवाती तूफान से बेमौसम हुई बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अबतक किसानों के खेत में सर्वे नहीं हो पाया है, जिससे उन्हें मुआवजा मिल सके। वहीं किसानों को फसल बीमा के बावजूद बीमा सर्वे भी नहीं हुआ और न ही बीमा का लाभ मिला। सरकार को इसपर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उपार्जन केंद्रों में एक महीने बाद किसानों का टोकन कट रहा है। किसानों के साथ ये सरकार मजाक कर रही है। पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि हमारे मास्टर प्लान पर सरकार ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए रोक लगा दिया। लेकिन खुद तीन साल में कुछ नहीं किया। अब सरकार बताएं कि कांग्रेस कार्यकाल के मास्टर प्लान में क्या गड़बड़ी थी।

एक्टिविस्ट आलोक शुक्ला ने भी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शुक्ला ने कहा कि 30 से 40 गांव पेंड्रावन जलाशय से सिंचित होता है। ऐसे में यहां अगर कंपनी खनन करती है तो बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर क्या वजह थी कि जो सरकार ने कंपनी को खनन करने के लिए एनओसी दे दी।

कृषि विवि में आज से दो दिवसीय राष्ट्रीय मखाना कार्यशाला

■ **कुलपति डॉ. चंदेल करेंगे कार्यशाला का शुभारंभ**



रायपुर। छत्तीसगढ़ में मखाना उत्पादन एवं प्रसंस्करण की संभावनाओं पर विचार मंथन हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड तथा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त तत्वावधान में कल गुरूवार 26 नवंबर 2026 को कृषि महाविद्यालय, रायपुर में दो दिवसीय राष्ट्रीय मखाना कार्यशाला का शुभारंभ होगा। स्वामी विवेकानन्द सभागार में कल प्रात: 11 बजे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के लगभग 250-300 किसान एवं महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्य तथा मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और उड़ीसा के किसानों सहित कृषि, उद्यानिकी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस अवसर पर मखाना के विभिन्न उत्पादों एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर आयोजित एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।

कार्यशाला में मखाना की उन्नत खेती, प्रसंस्करण, मशीनीकरण, मूल्य संवर्धन, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा विपणन से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञ जानकारी देंगे। राष्ट्रीय मखाना संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. मनोज कुमार, प्रसंस्करण के मुख्य वैज्ञानिक धमेन्दर कुमार, बिहार के मखाना विशेषज्ञ डॉ. विद्यानन्द झा, केंद्रीय फसल-कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. राजेश कुमार विश्वकर्मा सहित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉ. घनश्याम दास साहू एवं डॉ. गजेन्द्र चन्द्राकर विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देंगे।

कार्यशाला का उद्देश्य किसानों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों एवं अन्य हितधारकों को एक मंच पर लाकर मखाना की उन्नत खेती, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन से जुड़ी नवीन तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराना तथा प्रदेश में मखाना क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड द्वारा प्रक्षेत्र विस्तार, बीज उत्पादन, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, बाजार एवं निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान एवं सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में छत्तीसगढ़ को शामिल किए जाने के बाद प्रदेश में मखाना उत्पादन के विस्तार की संभावनाएं बढ़ी हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के सहयोग से वर्तमान में प्रदेश में 133.862 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना की खेती की जा रही है, जिसमें 96.438 हेक्टेयर तालाबों तथा 37.424 हेक्टेयर कम गहरे पानी वाले खेतों में है। प्रदेश में 15 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना बीज उत्पादन कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है। धमतरी, रायपुर (आरंग), बालोद, महासमुंद, गरियाबंद और जांजगीर-चांपा प्रमुख मखाना उत्पादक जिले हैं।

बैलाडीला में बेमौसम लैंडस्लाइड के पीछे देवी-देवता की उपेक्षा, अपमान!

अरविंद नेताम ने आदिवासियों की आस्था से खिलवाड़ का लगाया आरोप



रायपुर। बेमौसम बैलाडीला में लैंडस्लाइड के पीछे देवी-देवता की उपेक्षा और अपमान है। केंद्रीय मंत्री रह चुके छत्तीसगढ़ के बड़े आदिवासी चेहरा अरविंद नेताम ने यह बात कहते हुए कहा कि इसके पहले भी यहाँ कार्य एलाट हुआ था, लेकिन उसे बंद कर दूसरी जगह शिप्ट किया गया। लेकिन अब सब को दरकिनार कर हमारे देवी-देवताओं को निकाल कर अपमानित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि आपकी आस्था आस्था है, और हमारी आस्था का क्या?

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने बिबोल टोप्पो बनाम ओडिशा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के तीन गांवों में खनन/सीमेंट परियोजना के लिए डालमिया सीमेंट के 273।57 एकड़ जमीन के भूमि अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण (LARR Act, 2013 की धारा 41(3)) के लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य कानूनी सुरक्षा है। जहाँ ग्राम सभा ने प्रस्ताव खारिज कर दिया हो, वहाँ आगे बढ़ना कानून का उल्लंघन है। 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति ज़रूरत है। अरविंद नेताम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार खाका बनाया जा रहा है। इसे छत्तीसगढ़ के कोने-कोने तक पहुँचने काम किया जा रहा है। जैसे मनमाना अधिग्रहण ओडिशा में हो रहा है, वैसा ही छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। पेसा कानून को तोड़-मरोड़ के रास्ता निकाल लिया जाता है।

धान खरीदी में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप, सरकार जारी करे श्वेत पत्र: दीपक बैज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी, किसानों की समस्याओं और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश सरकार पर धान खरीदी में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान से संबंधित 56 प्रतिशत चावल अब तक जमा नहीं हो पाया है। बैज ने इसे छत्तीसगढ़ में चावल का बड़ा भ्रष्टाचार बताते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

दीपक बैज ने कहा कि करीब 50 मीट्रिक टन धान कस्टम मिलिंग के लिए दिया गया था, लेकिन राइस मिलरों से चावल वापस जमा नहीं हुआ है। उनका आरोप है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने भी सरकार को पूरी राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में सरकार अपने ऋण का भुगतान कैसे करेगी? उन्होंने कहा कि आम जनता की गाढ़ी कमाई को सरकार बर्बाद कर रही है और पूरे मामले की वास्तविक स्थिति जनता के सामने आनी चाहिए।

17 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर भी दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में सरकार ने कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं और जेन-जी के नए मतदाताओं के नाम भी नहीं जोड़े जा रहे हैं। सरकार अपनी एंटी-इनकंबेंसी छिपाने के लिए लोगों को मतदान से रोकना चाहती है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने सरगुजा में हार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदार बताया था, इस पर बैज ने कहा कि कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है। भाजपा को पहले अपना घर देखना चाहिए।



मास्टर प्लान में बदलाव की तैयारियों पर दीपक बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार को बने तीन साल हो चुके हैं। इतने समय में सरकार क्या कर रही थी? उन्होंने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान के नाम पर सरकार केवल भ्रष्टाचार करने में लगी है।

सर्व आदिवासी समाज की बैठक और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के निर्णय पर बैज ने कहा कि आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आवाज उठा रहा है। सरकार आदिवासियों के अधिकार छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यूसीसी और आरक्षण जैसे मुद्दों पर आदिवासी समाज सरकार का विरोध कर रहा है। कई आदिवासी आज भी जेलों में बंद हैं। बैज ने दावा किया कि ओबीसी वर्ग भी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और कर्मचारी भी विरोध का बिगुल फूंक चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दो वर्षों में सरकार के सामने राजनीतिक चुनौतियां और बढ़ेंगी।

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू होने के बाद भी सामने आ रहे मामलों को लेकर दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून लागू करते समय प्रदेश में शांति स्थापित करने का दावा किया था, लेकिन इसके बाद भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि इन घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा?

कांग्रेस द्वारा किसान हेल्प डेस्क शुरू किए जाने को लेकर हो रही सियासत पर बैज ने कहा कि भाजपा को वास्तव में किसानों और धान की चिंता है तो उसे खेतों में जाकर स्थिति देखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बारिश से किसानों का धान भीग चुका है और खेतों में पानी भरा हुआ है, लेकिन सरकार केवल कागजों में सर्वे करा रही है। किसानों को अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और क्या धान की कीमत का सही भुगतान सुनिश्चित होगा? बैज ने कहा कि सरकार की जगह कांग्रेस किसानों की मदद के लिए आगे आ रही है।

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को एआईसीसी सचिव की जिम्मेदारी से हटाए जाने पर भाजपा की ओर से किए गए तंज पर भी दीपक बैज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अजय चंद्राकर पर निशाना साधते हुए कहा कि शहीद कौन हुआ है, इसका उदाहरण अजय चंद्राकर से बड़ा कोई नहीं हो सकता।

सपा की पहली लिस्ट से नाराज हुई कांग्रेस

अंकित सिंह

समाजवादी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए पांच उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अपने मौजूदा पांचों विधायकों को उनकी ही सीटों से टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। इन उम्मीदवारों में सहारनपुर के बेहट विधानसभा क्षेत्र (01) से उमर अली खान, सहारनपुर (04) से आशु मलिक, शामली के कैराना (08) से नाहिद हसन, अमरोहा (41) से महबूब अली और ललितपुर (226) से ज्योति लोधी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा घोषित पांच सीटों में से, बेहट और सहारनपुर की दो ऐसी सीटें थीं, जिन्हें कांग्रेस भी गठबंधन की बातचीत के तहत मांग रही थी। हालांकि, सपा ने इन सीटों पर अपने मौजूदा विधायकों को ही मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने बेहट और सहारनपुर को उन 181 विधानसभा क्षेत्रों की सूची में शामिल किया था, जिसे उसने पहले सपा को सौंपा था। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में, समाजवादी पार्टी ने इन दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। सीट बंटवारे को लेकर शुरू हुआ मतभेद अब खुलकर नाराजगी के रूप में सामने आ गया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बातचीत करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। इसकी तात्कालिक वजह 24 नवंबर को समाजवादी पार्टी द्वारा अपने पांच उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा करना बनी, जबकि उस समय कांग्रेस के साथ बातचीत चल ही रही थी। लोकसभा में सहारनपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले मसूद के लिए, यह कदम महज चुनावी घोषणा से कहीं बढ़कर था। यह इस बात का सवाल था कि कांग्रेस को उसके गठबंधन सहयोगी से कितना सम्मान मिल रहा है। मसूद ने कहा, क्या हम भिखारी हैं? क्या आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे - कि हमने आपसे सीटों की मांग भी नहीं की और आपने 26 सीटों की घोषणा कर दी? हमने तो आपसे सीटों की मांग भी नहीं की थी। उन्होंने सपा के इस एकतरफा रवैये पर अपनी नाराजगी जताई। मसूद ने सवाल किया कि जब आपने मेरे खिलाफ यह बयान दिया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से, या फिर बीजेपी से? यह तो तय होना चाहिए न कि आप बीजेपी से लड़ना चाहते हैं या हमसे? ऐसे में, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ? यह घोषणा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच चल रही सीट-बंटवारे की बातचीत के दौरान हुई है। बातचीत के दो दौर के बाद, सपा ने कांग्रेस को उन सीटों में से 26 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है, जिन्हें कांग्रेस ने प्राथमिकता दी थी। हालाँकि, गठबंधन की पूरी रूपरेखा अभी तय होनी बाकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगे और बातचीत करने की बात कही है। उनका तर्क है कि सीटों का बंटवारा केवल निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के आधार पर नहीं, बल्कि चुनावी संभावनाओं और जनता की उम्मीदों के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी, उनकी पार्टी कांग्रेस के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर सकती है। इमरान मसूद के लिए, यह विवाद राजनीतिक जगह और उस क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति से भी जुड़ा है, जहाँ पार्टी की काफी अहम हिस्सेदारी है। मसूद लोकसभा में सहारनपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। राज्य संगठन में उन्हें आगे लाने का पार्टी का फैसला, पश्चिमी यूपी में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना गया था। 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत के बाद, कांग्रेस के लिए सहारनपुर का महत्व और बढ़ गया है।

देश का पथप्रदर्शक : हमारा संविधान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

26 नवंबर... 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हमारे संविधान को अंगीकार किया था। आज हम डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों का स्मरण करते हैं। उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने एक आधुनिक संविधान के निर्माण में भारत की समृद्ध परंपराओं और हमारी सभ्यता के अनुभव को भरपूर स्थान दिया।

भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में, जहां अनेक पंथ हैं, भाषाएं हैं, रीति-रिवाज हैं, विचार परंपराएं हैं, वहां ये बहुत जरूरी है कि संविधान की गूंज संसद और अदालतों की चारदीवारी से कहीं आगे तक पहुंचे। हमारा प्रयास रहा है कि जन-जन की चेतना से, विशेषकर हमारे युवाओं से संविधान का जुड़ाव और गहरा हो। इससे राष्ट्रीय एकता की वो भावना और मजबूत होगी, जो भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ एक दशक पहले हमारी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था।

हमारा संविधान मेरे साथ करोड़ों भारतीयों की जीवन यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है। बचपन के वो साधारण हालात, जीवन के वो संघर्ष, जब भी मैं उस दौर को याद करता हूं, संविधान के प्रति मेरा हृदय अपार कृतज्ञता से भर जाता है। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बालक, जिसे विरासत में कोई विशेषाधिकार या सुविधा नहीं मिली, एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सेवा का दायित्व संभाल सकता है, ये हमारे संविधान की असाधारण शक्ति का प्रमाण है। ये हमारे संविधान की ही देन है कि आज किसी व्यक्ति के जन्म की परिस्थितियां उसके भविष्य की सीमाएं तय नहीं करतीं। हमने अपने विनम्र प्रयासों से संविधान को और अधिक सशक्त बनाकर कृतज्ञता के इस ऋण को चुकाने की कोशिश की है।

प्रख्यात संवैधानिक विशेषज्ञ ग्रैनविले ऑस्टिन ने हमारे संविधान को 'first and foremost a social document' बताया था। सामाजिक और आर्थिक न्याय की भावना हमारे संविधान के मूल में समाहित है। ऐसे में संविधान निर्माताओं के इस बहुमूल्य सपने को साकार करने के प्रयासों से अधिक संतोषजनक और क्या हो सकता है?

विश्व बैंक की हाल में आई एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के करीब 50 करोड़ लोग अत्यंत



गरीबी से बाहर निकले हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे अभावों से मुक्ति पाकर आज करोड़ों माता-पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के सपने देख पा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से किसी परिवार को झोपड़ी से निकलकर पक्के मकान में गृह प्रवेश का अवसर मिलता है, तब गरिमापूर्ण जीवन जीने का संवैधानिक संकल्प सही मायनों में साकार होता है। जब उज्ज्वला योजना किसी मां को धुएं से भरी रसोई की तकलीफों से मुक्ति दिलाती है, तब हम समानता और जनकल्याण के आदर्शों को आगे बढ़ाते हैं।

जब आयुष्मान भारत की वजह से किसी गरीब परिवार को कर्ज की चिंता किए बिना अच्छा इलाज मिलता है, तब उसके जीवन में सामाजिक न्याय का संकल्प साकार होता है। जब मुद्रा योजना और पीएम स्वनिधि के तहत छोटे उद्यमियों और रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी के ऋण मिलता है, तब आर्थिक न्याय की संवैधानिक भावना जमीन पर उतरती है। जब डिजिटल टेक्नोलॉजी, रूपे कार्ड और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म तक हर नागरिक की पहुंच होती है, तब समावेशिता का संवैधानिक आदर्श साकार होता है। पहले इसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक ही सीमित कर दिया गया था। संविधान की शक्ति से सामान्य मानवी को सशक्त बनाने के आज ऐसे कई और उदाहरण हैं।

हमारी सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को भी इसी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। 101वें संविधान संशोधन से जीएसटी जैसे बड़े सुधार का रास्ता खुला, जिसका लंबे समय से इंतजार था। 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। इससे समाज के वंचित वर्गों का वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ।

हमारी सरकार द्वारा किए गए 103वें संविधान संशोधन को भी लोगों ने सराहा। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। इससे लंबे समय तक आरक्षण व्यवस्था के दायरे से बाहर रहने वाले समुदायों को लाभ हुआ। आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था।

1950 के बाद पहली बार आज हमारे संविधान का अपडेटेड वर्जन आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध है। इससे हमारा संविधान जनसामान्य के और करीब आया है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी हमारे देश में 1860 के दशक में, गुलामी के दौर में बनी दंड संहिता ही लागू रही। भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से हमने अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मौलिक बदलाव लाने का प्रयास किया है। गुलामी के दौर की व्यवस्था में दंड पर जोर था। भारतीय न्याय संहिता का जोर नागरिक आधारित व्यवस्था और न्याय पर है।

बीते एक दशक में हमने नागरिकों के कर्तव्यों पर विशेष बल दिया है। हमारी सभ्यता में समाज के हर व्यक्ति को उसकी भूमिका से जुड़े कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोध कराने की परंपरा रही है। स्वच्छ भारत से लेकर जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण तक, अनेक जन आंदोलनों में हमें कर्तव्य की इसी भावना के दर्शन हुए हैं।

यहां मैं एक और सच्चाई देशवासियों के साथ साझा करना चाहता हूं। हमारे इतिहास में ऐसे अवसर भी आए हैं, जब उन्हीं लोगों ने संविधान को कमजोर करने का रास्ता चुना, जिन पर इसकी रक्षा का दायित्व था। विडंबना देखिए कि ये वही लोग हैं, जिन्हें पांच दशकों तक देश की बागडोर संभालने का अवसर मिला।

इस वर्ष, 1951 में हुए पहले संविधान संशोधन के 75 साल पूरे हो चुके हैं। उस समय देश में एक ऐसी सरकार थी, जिसे जनता ने चुनकर नहीं भेजा था। उस सरकार ने अंतरिम संसद में अपने बहुमत का इस्तेमाल करके नागरिकों की मौलिक आजादी छीन ली थी। यह संशोधन देश के पहले आम चुनाव से कुछ ही महीने पहले किया गया था। इससे साफ है कि इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना और लोगों के विरोध की आवाज को दबाना था।

इसी प्रकार आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संविधान संशोधन के भी 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस संशोधन ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित किया और देश की संस्थाओं के बीच शक्तियों के संतुलन को बुनियादी रूप से बदल दिया। मैं युवाओं से यह भी आग्रह करूंगा कि वे 38वें और 39वें संविधान संशोधनों का भी अध्ययन करें। इससे वे समझ सकेंगे कि सत्ता की लालची और संविधान-विरोधी सोच रखने वाली सरकार किस स्तर तक जा सकती है।

चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए बार-बार आर्टिकल 356 का दुरुपयोग भी हमारे इतिहास का एक चिंताजनक अध्याय है। एक राजनीतिक दल के नाम करीब सौ बार आर्टिकल 356 थोपने का रिकॉर्ड दर्ज है। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने तो इस मामले में अर्धशतक भी लगाया है। हमारे संविधान निर्माताओं की अपेक्षा थी कि पूरे भारत में संविधान अपने मूल स्वरूप और अपनी मूल भावना के साथ लागू हो। लेकिन 70 साल से भी अधिक समय तक आर्टिकल 370 और 35-ए के कारण जम्मू-कश्मीर में हमारा पूरा संविधान लागू नहीं हो पाया। वहां एससी, एसटी, ओबीसी समाज और महिलाओं के अधिकारों का हनन होता रहा। 2019 में जाकर इस ऐतिहासिक अन्याय का अंत हुआ।

दशकों तक देश के अनेक हिस्सों में, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, नक्सलियों ने बंदूक के दम पर सबसे गरीब व्यक्ति को उन अधिकारों से वंचित रखा, जो हमारे संविधान ने उसे दिए हैं। इस वर्ष नक्सलवाद के खात्मे से मुझे विशेष संतोष मिला है। अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी बिना किसी भय के अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। हथियारी नक्सली समाप्त होने के बाद अब केवल दिमागी नक्सली बचे हैं। वो आज के दौर की वास्तविकताओं से कोसों दूर हैं और देश की विकास यात्रा को पटरी से उतारने की कोशिशों में लगातार जुटे हैं।

ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी ओबीसी आरक्षण में कटौती करके मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। हमारे संविधान निर्माता, विशेषकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, इसके पूरी तरह खिलाफ थे।

हमारे संविधान की यात्रा उन असाधारण महिलाओं के स्मरण के बिना भी अधूरी है, जिन्होंने इसे आकार देने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इस साल के शुरू में जो हुआ, उसने हम सभी को शर्मसार कर दिया। नारीशक्ति को विधायी संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से लाए गए विधेयक को विपक्ष के एक प्रमुख दल ने पारित नहीं होने दिया। एक बार फिर उसने दिखाया है कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति उसके मन में कितना कम सम्मान है। मैं देश की नारीशक्ति को भरोसा दिलाता हूं कि उन्हें न्याय दिलाने के हमारे संकल्प को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय



24- दिङ्नाग सम्प्रदाय का न्यायवाद

गतांक से आगे...

क्योंकि विचार-शक्ति द्वारा बाह्य वस्तुओं को दिये हुये आकार परमार्थत: (transcen-dentally) मानस (ideal) ही हैं। दिङ्नाग के सिद्धान्त की काण्ट के दर्शन से समता स्पष्ट है, क्योंकि काण्ट के अनुसार यद्यपि बाह्य जगत् में वस्तु का अपना यथार्थ स्वरूप (thing in itself or noumenon) विद्यमान है, परन्तु दृश्यमान जगत् (phenomenal world) को आकार और स्वरूप हमारी विचार शक्ति (understanding) ने ही दिया है।

25 - पूर्वमीमांसा

पूर्वमीमांसा और अर्थविज्ञान : वेद के तीन भाग हैं- संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद् । इनमें मूल वेद अर्थात् मंत्र भाग ऋग्वेद आदि संहिताओं के नाम से प्रसिद्ध है।

जिन ग्रन्थों में यज्ञसम्बन्धी कर्मकाण्ड का वर्णन है, वे ब्राह्मण ग्रन्थ कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के साथ ब्राह्मण ग्रन्थ जुड़े हुये हैं। इन्हीं ब्राह्मण ग्रन्थों के कुछ अंश आरण्यक कहलाते हैं और आरण्यकों के अंश उपनिषद् हैं (देखो परिच्छेद 2)।

उपनिषद् ब्राह्मणों से अलग इसलिये गिने जाते हैं जहाँ ब्राह्मणों का विषय कर्मकाण्ड अथवा यज्ञ है, उपनिषदों का विषय ब्रह्मविद्या या आत्मज्ञान है। वेद के इन दो भागों- ब्राह्मण और उपनिषद् से क्रमश: सम्बन्ध रखने वाले दो दर्शन हैं उनमें एक वेद के पूर्वभाग अर्थात् ब्राह्मणों से सम्बन्ध रखने के कारण पूर्वमीमांसा कहलाता है और जैमिनि उसका रचयिता है। दूसरा वेद के उत्तरभाग अर्थात् उपनिषदों से सम्बन्ध रखने के कारण उत्तरमीमांसा कहलाता है और बादरायण उसका रचयिता है। यह बतलाया जा चुका है कि मीमांसा शब्द सामान्यरूपेण दर्शन शास्त्र (फिलॉसफी) के लिये प्रयुक्त होता था, यह भी बतलाया जा चुका है।

क्रमश: ...

भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते थे वर्गीज कुरियन

अनन्या मिश्रा

आज ही के दिन यानी की 26 नवंबर को भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉ. वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। वह मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे। उन्होंने साल 1946 में गुजरात के आणंद में देश के सबसे पॉपुलर डेयरी ब्रांड अमूल की शुरूआत की थी। इसके अलावा वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के काम किया था। साथ ही लाखों किसानों को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया था।

केरल के कोझिकोड में एक समृद्ध सिरियन ईसाई परिवार में 26 नवंबर 1921 को वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। इनके पिता सरकारी सर्जन थे। कुरियन ने साल 1940 में चेन्नई के लोयोला कॉलेज से स्नातक और 1943 में गिंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। फिर साल 1948 में उन्होंने अमेरिका के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया।



साल 1949 में भारत लौटने पर सरकार के साथ बांड की अवधि को पूरा करने के लिए वर्गीज कुरियन को गुजरात के आनंद में डेयरी डिवीजन में भेजा गया। यहां पर कुरियन की मुलाकात त्रिभुवनदास पटेल से हुई। त्रिभुवनदास पटेल किसानों को एकजुट कर दूध सहकारी समितियों की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में वर्गीज कुरियन ने त्रिभुवनदास के साथ मिलकर साल 1946 में कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना की थी। जोकि बाद में अमूल बना।

इसके बाद कुरियन के दोस्त एच एम दयाला ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की तकनीक विकसित किया। इस तकनीक ने भारतीय डेयरी इंडस्ट्री को क्रांतिकारी बदलाव दिया। पहले सिर्फ गाय के दूध से यह प्रोडक्ट बनाए जाते थे, इस इनोवेशन ने भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

कुरियन के आनंद मॉडल को देखते हुए साल 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की। वहीं इस बोर्ड का कुरियन को पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर साल 1970 में शुरू हुए ऑपरेशन फ्लड ने भारत के दूध प्रोडक्शन को साल 1968-69 में 23.3 मिलियन टन से साल 2006-07 में 100.9 मिलियन टन बढ़ाया। फिर 25 सालों में 1700 करोड़ रुपए के निवेश से यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम बना। साल 1998 में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल किया।

डॉ वर्गीज कुरियन को साल 1963 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, साल 1989 में वर्ल्ड फूड प्राइज और फिर साल 1999 में पद्म विभूषण सहित कई सम्मान मिले।

वहीं 09 सितंबर 2012 को 90 वर्ष की आयु में गुजरात के नडियाद में डॉ वर्गीज कुरियन ने अंतिम सांस ली।

भारत-नेपाल की घटती दूरियाँ और बढ़ता व्यापार

अशोक भाटिया

इतिहास के पन्नों को पलटें तो भारत और नेपाल के संबंध केवल दो संप्रभु राष्ट्रों के बीच की औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं रहे हैं। यह रिश्ता सदियों पुरानी साझा विरासत, आध्यात्मिक एकात्मता और रोटी-बेटी के अटूट सामाजिक ताने-बाने से बुना गया है। हिमालय की गोद से निकलने वाली नदियाँ जिस तरह बिना किसी रोक-टोक के भारतीय मैदानों को सींचती हैं, उसी तरह दोनों देशों के नागरिकों के बीच का संवाद और स्नेह भी सदैव निर्बाध रहा है। 23 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा अयोध्या कैंट से जनकपुर धाम के बीच शुरू की गई नई साप्ताहिक एक्सप्रेस रेल सेवा, इस ऐतिहासिक मित्रता का आधुनिक विस्तार है।

रामायण काल से ही अयोध्या और जनकपुर का संबंध आस्था और संस्कृति की धुरी रहा है। त्रेतायुग में जो संबंध विवाह और संस्कारों के माध्यम से स्थापित हुआ था, इक्कीसवीं सदी के इस दौर में वही संबंध आधुनिक रेल नेटवर्क के माध्यम से विकास और व्यापार की नई परिभाषा गढ़ रहा है। लगभग छह सौ चार किलोमीटर लंबी यह रेल यात्रा जब अयोध्या से चलकर गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी और जयनगर होते हुए माता जानकी की नगरी जनकपुर धाम पहुंचेगी, तो यह केवल यात्रियों को ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाएगी, बल्कि दोनों देशों के बीच विचारों, संस्कृति और वाणिज्य के प्रवाह को भी अभूतपूर्व गति देगी। वर्ष 2022 में जयनगर और कुर्था के बीच शुरू हुई ब्रॉड-गेज रेल सेवा ने इस दिशा में जो नींव रखी थी, आज की यह नई सीधी ट्रेन सेवा उसे एक विराट स्वरूप प्रदान कर रही है।

किसी भी दो पड़ोसी देशों के बीच व्यापारिक संबंधों की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उनके बीच परिवहन और संपर्क के साधन कितने सुगम और किफायती हैं। नेपाल एक चारों ओर से



जमीन से घिरा हुआ यानी लैंडलॉक्ड देश है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक निर्भरता मुख्य रूप से भारतीय बंदरगाहों और सड़क मार्गों पर टिकी है। अब तक सड़क मार्ग से होने वाले परिवहन में समय और धन दोनों की अधिक खपत होती थी, जिसका सीधा असर नेपाल के बाजारों में वस्तुओं की कीमतों और उसके निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता पर पड़ता था। सीमा-पार रेल संपर्क का विस्तार इस समस्या का सबसे प्रभावी समाधान बनकर उभरा है। जयनगर-बर्दीबास रेल लाइन के निरंतर विस्तार और जोगबनी-विराटनगर रेल परियोजना की प्रगति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में भारत और नेपाल के बीच माल ढुलाई की लागत में भारी कमी आएगी। जब मालगाड़ियाँ सीधे भारतीय औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों से नेपाल के प्रमुख व्यापारिक शहरों तक पहुंचेंगी, तो इससे न केवल नेपाल के उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होंगी, बल्कि नेपाल के कृषि और लघु उद्योग उत्पादों को भी भारत के विशाल बाजार तक सीधी और सुगम पहुंच मिल सकेगी।

व्यापार के साथ-साथ पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें भारत और नेपाल के बीच अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास के बाद भारत में धार्मिक पर्यटन ने एक नई ऊंचाई को छुआ है। दूसरी ओर, नेपाल में जनकपुर धाम, पशुपतिनाथ और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी विश्व भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र हैं। अयोध्या और जनकपुर के बीच सीधी रेल सेवा की शुरुआत रामायण सर्किट की परिकल्पना को धरातल पर उतारने की दिशा में एक मील का पत्थर है। अब भारत के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालु बिना किसी सीमावर्ती झंझट या महंगे हवाई सफर के सीधे जनकपुर धाम तक की यात्रा कर सकेंगे। इसी तरह, नेपाल के नागरिकों के लिए भी अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों तक पहुंचना अत्यंत सहज हो गया है। पर्यटन की इस बढ़ती रफ्तार का सीधा लाभ सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों, होटल व्यवसायियों, हस्तशिल्प कारीगरों और छोटे व्यापारियों को मिलेगा, जिससे दोनों देशों के सीमावर्ती जिलों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं के अतिरिक्त, भारत और नेपाल के बीच बढ़ती यह कनेक्टिविटी क्षेत्रीय भू-राजनीति के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया के बदलते कूटनीतिक परिदृश्य में, जहाँ बाहरी शक्तियाँ इस क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए प्रयासरत हैं, भारत की नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी प्रथम की नीति की सफलता जमीनी परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर ही निर्भर करती है। नेपाल में नई पीढ़ी के नेतृत्व के उदय और बदलती राजनीतिक आकांक्षाओं के बीच, भारत द्वारा बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और रेल संपर्क के क्षेत्र में किया जा रहा निवेश दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को नई मजबूती प्रदान करता है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करते हुए उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता और विकास यात्रा में एक विश्वसनीय साझेदार की भूमिका निभा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। नेपाल में उत्पन्न होने वाली जलविद्युत का भारत को निर्यात और भारतीय ग्रिड के माध्यम से तीसरे देश तक बिजली पहुंचाने के समझौतों ने द्विपक्षीय व्यापार को एक नया आयाम दिया है।

हालांकि, उपलब्धियों के इस उत्साहजनक वातावरण के बीच हमें उन व्यावहारिक चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो अभी भी द्विपक्षीय व्यापार और संपर्क की पूर्ण क्षमता के दोहन में बाधक बनी हुई हैं। सीमा पर एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण के बावजूद, कई बार सीमा शुल्क यानी कस्टम प्रक्रियाओं की जटिलता, दस्तावेजी औपचारिकताओं में लगने वाला समय और बुनियादी ढांचे के रखरखाव से जुड़ी समस्याएं व्यापारियों के लिए अड़चन पैदा करती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित रक्सौल-काठमांडू रेल लाइन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को दुर्गम पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना दोनों सरकारों के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और आधुनिक तकनीक का उपयोग भी उतना ही आवश्यक है, ताकि व्यापार और आवागमन की सुगमता के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

भारत और नेपाल के संबंधों की वास्तविक शक्ति उनके नागरिकों के बीच के अटूट विश्वास और साझा भविष्य के सपने में निहित है। अयोध्या से जनकपुर तक दौड़ने वाली यह नई रेलगाड़ी केवल लोहे की पटरियों पर चलने वाला एक वाहन नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं, साझा इतिहास और उज्ज्वल आर्थिक भविष्य का वाहक है। जब दूरियाँ घटती हैं, तो केवल भौगोलिक फासले ही कम नहीं होते, बल्कि मन के संदेह भी मिटते हैं और सहयोग के नए रास्ते खुलते हैं। यदि दोनों देश इसी सकारात्मक ऊर्जा, राजनीतिक इच्छाशक्ति और पारस्परिक सम्मान के साथ अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाते रहें, तो भारत और नेपाल की यह साझेदारी न केवल दोनों देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और साझा समृद्धि का एक अनुकरणीय मॉडल भी प्रस्तुत करेगी।

आज का इतिहास

1885 पहली बार उल्कापिंड की तस्वीर ली गयी।
1932 महान् क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दस हजार रन बनाये।
1948 नेशनल कैडेट कोर की स्थापना हुई।
1949 आजाद भारत के संविधान पर संविधान सभा के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किया।
1960 भारत में पहली बार कानपुर एवं लखनऊ के बीच एसटीडी सेवा शुरु हुई।
1967 लिस्बन में बादल फटने से करीब 450 लोग मरे।
1984 इराक एवं अमेरिका ने कूटनीतिक संबंधों को पुन: स्थापित किया।
1996 मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यान मार्स ग्लोबल सर्वेयर को अंतरिक्ष में भेजा (7 नवम्बर); संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक के संदर्भ में आयल फ़ॉर फुड डील प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।
1997 पाक सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने मुख्य न्यायाधीश को निलम्बित किया।
1998 तुर्की के प्रधानमंत्री मेसुत यिल्माज ने संसद में अपनी सरकार के विश्वासमत हासिल नहीं कर पाने के बाद इस्तीफ़ा दिया, कंबोडिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हुनसेन को औपचारिक रूप से पुन: देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, माहे (सेशल्स) में इस्त्रायल की लीनोर अबार्गिल 1998 की मिस वर्ल्ड चुनी गईं।
1998 टोनी ब्लेयर ऑयरलैंड की संसद को संबोधित करने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने।
2001 नेपाल में 200 माओवादी विद्रोही मारे गये; देश में आपातकाल लागू।
2002 बीबीसी के सर्वेक्षण में विंस्टन चर्चिल महानतम ब्रिटिश नागरिक चुने गये।
2006 इराक बम धमाके में 202 लोगों की जान गई।
2008 भारत के मुंबई नगर में आत्मघाती आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने ताज होटल में घुसकर अनेक अतिथियों को बंधक बना लिया। इसे भारतीय सेना ने तीन दिनों की कार्यवाई के पश्चात् मुक्त करा लिया।
2008 मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में 164 लोग मरे, 250 से अधिक घायल।
2012 अरविंद केजरीवाल ने एक नये राजनैतिक दल आम आदमी पार्टी का गठन किया।

राजस्थान पंचायत चुनाव नतीजों में कुछ राष्ट्रीय संकेत भी छुपे हैं?

अजय बोकिल

राजस्थान में हाल में हुए पंचायतों के चुनाव के पूरे नतीजे अभी नहीं आए हैं, लेकिन अब तक के परिणाम सत्तारूढ़ भाजपा को चिंता में डालने वाले जरूर हैं। पंचायत चुनावों में प्रतिपक्षी कांग्रेस को भारी सफलता मिली है, जबकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र में एक छोटी पार्टी ने जीत दर्ज कराई है। इन नतीजों की व्याख्या ग्रामीण इलाकों में सरकार के प्रति नाराजी के रूप में की जा रही है।

ये नतीजे इसलिए भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि दो माह पहले हुए नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया था। राज्य के शहरी और ग्रामीण मतदाताओं के राजनीतिक रूझान में इतनी कम अवधि में इतना फर्क बेहद चौंकाने वाली बात है। भाजपा के लिए यह चिंता का कारण इसलिए भी है क्योंकि राज्य के कुल 5.45 करोड़ मतदाताओं में में 81.26 फीसदी वोटर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और यहीं पार्टी को करारा झटका लगा है।

राजनीतिक प्रेक्षक इन नतीजों को दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव और ढाई साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के आईने में देखने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या इन परिणामों का दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों पर भी कोई असर पड़ेगा या नहीं? क्या इन स्थानीय स्तर के चुनावों में कोई राष्ट्रीय संकेत भी छुपे हैं?

उधर भाजपा ने पंचायत चुनावों को जनादेश मानकर इनकी समीक्षा की बात कही है तो इस जीत से बम-बम कांग्रेस का कहना है कि यह डबल इंजन सरकार का जबर्दस्त फेलियर है। खास बात यह भी है कि पंचायत चुनाव भी ईवीएम से हुए थे, लेकिन नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की प्रामाणिकता पर अपने ही सवालों से अब कन्नी काट ली है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान के 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के नतीजे आ गए हैं। राज्य में कुल 41 जिले हैं, जिनमें से चार जिलों के नतीजे दिसंबर में आएंगे। राजस्थान में पंचायतों के चुनाव चार चरणों में हुए थे। कुल 7 हजार 543 पंचायत समिति सीटों और 1 हजार 275 जिला परिषद सीटों पर चुनाव हुए। अब तक प्राप्त नतीजों में पंचायत समिति की 7 हजार 543 सीटों में कांग्रेस 3 हजार 744 सीटों पर जीत चुकी थी, जबकि बीजेपी को 2 हजार 211 सीटें मिली थीं। जिला परिषद की 1,275 सीटों में कांग्रेस ने 690 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी 318 सीटों पर विजयी रही थी। पंचायत समिति चुनावों में निर्दलीय और छोटे दलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है।

हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी और भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी ने कई इलाकों में अपनी ताकत दिखाई है। कांग्रेस की इस बढ़त को ग्रामीण राजस्थान में पार्टी की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को करीब 14 लाख और पंचायत समितियों में 13.30 लाख वोटों से पीछे छोड़ दिया। पिछली बार कम वोट प्रतिशत के बावजूद ज्यादा सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार जिला परिषदों में भी पीछे रह गई।

नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी के कई मजबूत गढ़ों में सेंध लगाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने पंचायत समिति में जीत हासिल की है, जबकि सीएम के गृह जिले भरतपुर में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकार के मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को झटके लगे हैं। कांग्रेस ने मेवाड़ और मारवाड़ जैसे क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां बीजेपी का मजबूत जनाधार माना जाता है। बीजेपी ने दक्षिण राजस्थान के अजमेर और



उदयपुर में तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस इसे ग्रामीण मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत होने और बीजेपी सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजी का संकेत मान रही है।

मुख्यमंत्री के अलावा कुछ केन्द्रीय मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जोधपुर और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बीकानेर इलाके में बीजेपी को नुकसान हुआ है। इसी तरह राज्य के शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के सदस्य भी चुनाव में हार गए। जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर और सचिन पायलट के टोंक में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये चुनाव परिणाम इसलिए भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि तीन साल पहले राज्य में बीजेपी 200 में 115 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। तब भाजपा ने बतौर सीएम एक नया प्रयोग किया और पहली बार विधायक बने और प्रशासनिक अनुभव से शून्य भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया।

उनके पक्ष में कहा गया कि उन्हें संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। इसके अलावा ब्राह्मण कार्ड तो था ही। लेकिन उसके बाद हुए तमाम चुनाव नतीजों के देखें तो लगता नहीं कि भजनलाल शर्मा अपने राजनीतिक- प्रशासनिक नेतृत्व का लोहा मनवा पाए हैं। राज्य में भाजपा का ग्राफ लगातार गिरा ही है। पूर्व के दो लोकसभा चुनावों में लगभग क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा 2024 में 14 सीटें ही जीत सकी। जबकि कांग्रेस को 8 व 3 सीटें अन्य को मिली।

राजस्थान उन राज्यों में हैं, जहां मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस ही प्रतिद्वंद्वी दल हैं। हालांकि प्रदेश में दो माह पूर्व हुए नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन वह बहुत उत्साहजनक नहीं था। पंचायत नतीजों ने साबित किया कि ग्रामीण क्षेत्र में उसकी जमीन खिसकने लगी है।

अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तो अगला विस चुनाव और बाद में लोस चुनाव जीतना पार्टी के लिए टेढ़ी खीर होगा। हालांकि उस समय चुनाव में कौन से मुद्दे और नरेटिव हावी होंगे, यह अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मतदाताओं की नाराजी दूर नहीं हुई तो यह नतीजे भाजपा के लिए खतरे के लिए घंटी हैं।

यकीनन ये चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए खुश होने के हैं। पार्टी मान रही है कि देश में भाजपा सरकारों, उनकी कार्यशैली और नेतृत्व के प्रति यह जनमानस में धीरे-धीरे बदलाव का संकेत है। कांग्रेस इस नरेटिव को वोट में तब्दील करने में कामयाब रही तो पार्टी के अच्छे लौट सकते हैं।

बशर्ते कि नरेटिव गढ़ने जैसी दक्षता और विजन संगठन को मजबूत करने में भी दिखे। कांग्रेस तमाम विपक्षी दलों को यह मनवाने में तो सफल हो ही गई है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प केवल राहुल गांधी ही हो सकते हैं और कांग्रेस के बगैर विपक्ष का कोई मोर्चा कामयाब नहीं हो सकता।

हालांकि, आगामी चुनावों में जीत का परचम लहराने की मंशा को हकीकत में बदलने का सफर लंबा है। राजस्थान के पंचायत चुनाव परिणामों को इस दृष्टि से भी जांचना जरूरी है कि यह कांग्रेस के प्रति सकारात्मक वोट है या फिर भाजपा के खिलाफ नकारात्मक वोट है? यानी लोग सचमुच सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या फिर वो केवल भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में हारना भाजपा के लिए इसलिए ज्यादा परेशानी कारण है, क्योंकि वोटरों की बड़ी तादाद इन्हीं इलाकों में रहती हैं।

कुछ जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनावों नतीजों को विस अथवा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये नितांत स्थानीय स्तर और स्थानीय मुद्दों को लेकर होते हैं। यहां व्यक्तिगत राजी- नाराजी भी काफी काम करती है। जबकि विस और लोस चुनाव व्यापक परिप्रेक्ष्य लिए होते हैं। यह जरूरी नहीं कि मतदाता उसी मानस से वोट करे, जैसे कि वह पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में करता है।

यह तर्क अपनी जगह सही है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी की इतने बड़े पैमाने पर हार कोई मामूली बात नहीं है। वह भी तब कि जब कांग्रेस ने जीत हासिल करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। राजनीतिक विश्लेषक इन परिणामों को अगले साल पांच राज्यों और खासकर यूपी के संदर्भ में देखने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन यूपी की राजनीति राजस्थान से अलग है। हालांकि, जातीय समीकरण दोनो जगह मायने रखते हैं। राजस्थान में पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने कई जातियों को साथ रखकर बेहतर समीकरण बनाया। उसने अनुसूचित जाति, जाट, गुर्जर और मीणा समुदायों के बीच अपना पारंपरिक समर्थन मजबूत किया, साथ ही भाजपा के कोर माने जाने वाले राजपूत वोट बैंक में भी सेंध लगाई। जबकि भाजपा ऐसा करने में नाकाम रही। या तो वह अति आत्मविश्वास में डूबी रही या फिर उसने जमीन पर आपसी कलह को अनदेखा किया। बहरहाल भाजपा नेता सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहें, पार्टी आलाकमान ने इन परिणामों को गंभीरता से लेते हुए पूरी रिपोर्ट मांगी है। चुनाव परिणामों की समीक्षा का काम संजय भाटिया को सौंपा गया है। पार्टी अगले चुनाव को मद्देनजर कौन से बड़े कदम उठाती है, यह देखने की बात होगी।

रूस के खिलाफ सफल रहा यूक्रेन का ऑपरेशन विवाल्दी

नीरज कुमार दुबे

युद्ध की दुनिया तेजी से बदल रही है। अब मैदान में सिर्फ सैनिक, टैंक और बंदूकें ही नहीं लड़ रहे, बल्कि अत्याधुनिक ड्रोन और रोबोट भी दुश्मन पर हमला करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसी तकनीक के सहारे सैनिक दूर रहकर भी दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ऑपरेशन विवाल्दी में इसी नई युद्ध रणनीति को अपनाया है, जहां इंसानी सैनिकों और मशीनों के तालमेल ने रूसी सेना के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। पूर्वी यूक्रेन के युद्धक्षेत्र में इस ऑपरेशन ने आधुनिक सैन्य तकनीक की ताकत का प्रदर्शन किया। यूक्रेन ने जमीन पर चलने वाले रिमोट कंट्रोल रोबोटों को मशीनगन, ग्रेनेड लॉन्चर और विस्फोटकों से लैस कर रूसी ठिकानों पर हमले किए। कुछ रोबोटों का इस्तेमाल बारूदी सुरंगों से भरे रास्तों को साफ करने के लिए किया गया। यहां तक कि क्वाडकॉप्टर बमवर्षक ड्रोन की मदद से लड़ाकू रोबोटों को रूसी सेना की अग्रिम पंक्तियों के पीछे पहुंचाया गया। यूक्रेनी सेना के मुताबिक, युद्ध में इस तरह का इस्तेमाल एक नई शुरुआत थी। इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था इंसानी सैनिकों और मशीनों के बीच तालमेल। यूक्रेनी सैनिक छोटे-छोटे समूहों में आगे बढ़ते रहे, जबकि आसमान में मौजूद ड्रोन उनकी सुरक्षा और हमले की जिम्मेदारी संभालते रहे। जिन रूसी बंकरों और ठिकानों में प्रवेश करना सैनिकों के लिए बेहद खतरनाक था, वहां पहले ड्रोन से हमले किए गए। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन और संचार संकेतों को बाधित करने का काम किया। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन विवाल्दी का लक्ष्य केवल रूसी सैनिकों को पीछे हटाना नहीं था, बल्कि पूर्वी यूक्रेन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों के उस रक्षा क्षेत्र को बचाना था, जिसे फोर्ट्रेस बेल्ट कहा जाता है। रूस इस क्षेत्र को घेरने के लिए दो दिशाओं से दबाव बना रहा था। यूक्रेन के जवाबी अभियान ने इस घेराबंदी की कोशिश को बाधित कर दिया। अक्टूबर में समाप्त हुए इस अभियान में यूक्रेनी सेना ने लगभग 277 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस हासिल करने का दावा किया। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन की योजना चार चरणों में तैयार की गई थी। पहले चरण में यूक्रेनी नियंत्रण वाले इलाकों में घुसपैठ कर चुके रूसी सैनिकों को खोजकर बाहर निकाला गया। इसके बाद मध्यम दूरी के हमलावर ड्रोन से रूसी आपूर्ति मार्गों और कमांड पोस्ट को निशाना बनाया गया। तीसरे चरण में यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों ने रूसी निगरानी और हमलावर ड्रोन को निशाना बनाकर आसमान में अपनी गतिविधियों के लिए रास्ता बनाया। अंतिम चरण में छोटे-छोटे सैन्य दस्तों ने ड्रोन से भरे बेहद खतरनाक युद्धक्षेत्र में प्रवेश कर रूसी सैनिकों को रणनीतिक ठिकानों से पीछे हटने पर मजबूर किया। इस पूरी रणनीति में यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स की अहम भूमिका रही। ब्रिगेडियर जनरल एंड्री बिलेस्त्की के मुताबिक, पारंपरिक युद्ध में किसी सैन्य टुकड़ी के पास कुछ दर्जन बख्तरबंद वाहन और सीमित कमांड पोस्ट होते थे, लेकिन अब एक ही युद्धक्षेत्र में आसमान और जमीन पर एक हजार तक सैन्य संसाधनों का संचालन संभव है। पैदल सैनिकों को भी अब रोबोटिक सिस्टम के साथ युद्ध संरचना का हिस्सा बनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेशएक्स की सैन्य संचार सेवा स्टारशिल्ड का भी इस्तेमाल किया गया। इसी तकनीक के जरिए कई हमलावर ड्रोन और मानवरहित सैन्य प्रणालियों को नियंत्रित किया गया।

बांग्लादेश में राजनीतिक प्रतिशोध चरम पर

सुबीर भौमिक

शुक्रवार रात (20 नवंबर) को, सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के समर्थकों की हथियारबंद भीड़ ने नरैल के कई गांवों पर हमला कर दिया और 400 से अधिक घरों में आग लगा दी। इस इलाके में हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी रहती है, खासकर 'घोषपाड़ा' और 'साहापाड़ा' में, जिन्हें इस भीड़ के गुस्से का सबसे ज्यादा शिकार होना पड़ा। दो हिंदू महिलाओं का जबरन अपहरण कर लिया गया और हिंदुओं के 50 से ज्यादा घरों को जला दिया गया।

इस हमले में कई स्थानीय ग्रामीण घायल हो गए। गौरतलब है कि मंगलवार (शेख हसीना को न्यायालय द्वारा सुनाई गई मौत की सजा की बरसी पर) रात से ही बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में हुई आगजनी, तोड़फोड़ और कॉकटेल बम विस्फोटों में बसों, पुलिस स्टेशनों, बीएनपी कार्यकर्ताओं के घरों, पार्टी कार्यालयों और ग्रामीण बैंक की शाखाओं पर हमले हुए। बुधवार को गोपालगंज में व्यापक हिंसा देखने को मिली, जहां राजमार्गों पर गाड़ियों में आगजनी की गई और पेड़ काट कर आवागमन को बाधित करने की कोशिश की गई। उसी दिन विरोध प्रदर्शन से लौटते समय हुए हमले में बीएनपी के दो नेताओं की हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि हमलावर प्रतिबंधित अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता थे। ये प्रदर्शन और हिंसा भारत से शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर बढ़ते तनाव के बीच हुए। तोड़फोड़ और अशांति फैलाने के आरोप में अवामी लीग के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पूर्व शिक्षा मंत्री नूरुल



इस्लाम नाहिद भी शामिल हैं। अवामी लीग ने 19 नवंबर, को देशव्यापी बंद (लॉकडाउन) का फैसला किया था, क्योंकि सरकार की ओर से हसीना की उस अपील को खारिज कर दिया गया, जिसमें उन्होंने दिसंबर में देश लौटने की अपनी योजना को आसान बनाने के लिए पासपोर्ट जारी करने की मांग की थी।

शुक्रवार को बीएनपी समर्थकों की भीड़ को नरैल में पार्टी के वरिष्ठ नेता रूहुल कबीर रिजवी ने 'अवामी लीग को सबक सिखाने' के लिए उकसाया था। रिजवी का यह बयान ठीक उस समय आया, जब तारिक रहमान ने सड़कों पर हो रही हिंसा के लिए अवामी लीग को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि 'यह सीमा पार बैठे उनके आकाओं को खुश करने के लिए किया गया है।'

हालांकि रहमान ने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर भारत की ओर था, और उन्होंने बांग्लादेश में फैली हिंसा के इस नए दौर के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बीएनपी के सांसदों से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौटने और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का मुकाबला करने के लिए जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर सक्रिय रूप से मौजूद रहने को कहा था। उन्होंने सांसदों से केवल प्रशासन पर निर्भर रहने के बजाय खुद भी सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की थी। वास्तव में प्रधानमंत्री रहमान, जिन्हें पदभार संभाले अभी नौ महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, अवामी लीग द्वारा हाल ही में की गई हड़तालों और बंद पर जनता की व्यापक प्रतिक्रिया से स्पष्ट रूप से घबराए हुए हैं। यह सब तब हो रहा है, जब अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने और कानूनी कार्रवाई का सामना करने की योजना है। अवामी लीग, जो अब भी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही प्रतिबंधित है। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर काम किया था। लेकिन नई चुनी गई बीएनपी सरकार ने संसद में इस प्रतिबंध को औपचारिक रूप देकर एक कदम और आगे बढ़ा दिया। इस स्थिति में अवामी लीग के सामने प्रतिबंध हटाने की अपनी मांग के समर्थन में सड़कों पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उनके हजारों नेता और कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाकर जेलों में बंद कर दिया गया है। कई लोग मारे गए हैं या जीवन भर के लिए अपंग हो गए हैं; यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया है। लीग के हजारों समर्थक पलायन कर भारत आ गए, और कई लोगों ने भीड़ के हमलों या गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने गृह जिलों को छोड़ दिया है। ऐसे हालात में, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने का फैसला किया है। ऐसा करके वह अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। बीएनपी सरकार उनके लौटने को रोकना चाहती है, क्योंकि उसे डर है कि इससे जनता का गुस्सा भड़क सकता है। यही वजह है कि उनके वकीलों की औपचारिक मांग के बावजूद, सरकार ने उन्हें यात्रा दस्तावेज देने से इन्कार कर दिया है। ढाका चाहता है कि शेख हसीना को औपचारिक रूप से बांग्लादेश प्रत्यर्पित किया जाए, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि हसीना खुद वापस लौटना चाहती हैं, और नई दिल्ली अभी इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या उन पर चला मुकदमा कानून की उचित प्रक्रिया के तहत हुआ था या नहीं। भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत, मेजबान देश को फैसले की निष्पक्षता को लेकर संतुष्ट होना चाहिए। दिल्ली का तर्क है कि प्रत्यर्पण की जरूरत तभी पड़ती है, जब कोई व्यक्ति न्याय का सामना करने के लिए वापस जाने को तैयार न हो, जबकि हसीना के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है।

शेख हसीना की प्रस्तावित वापसी से पहले, जिस पर अब भी कई लोगों को संदेह है, अवामी लीग ने लगातार आंदोलन चलाने की घोषणा की है। अवामी लीग पर से प्रतिबंध हटाकर राजनीतिक सुलह का रास्ता अपनाया जा सकता था, लेकिन इसके बजाय बीएनपी सरकार ने सीधे टकराव का रुख अपना लिया है। उसने अपने कार्यकर्ताओं को उस तरह की व्यापक हिंसा करने के लिए खुला छोड़ दिया है, जैसी हिंसा शुक्रवार को नरैल में देखने को मिली।

क्या चीन की चालबाजियां समझ रहे हैं नेपाल के पीएम बालेन शाह?

विकास मिश्रा

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की भारत यात्रा को निश्चित ही दोनों देशों के लिए सुखद परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए। किसी एक यात्रा में सभी मसलों का हल हो जाए यह संभव नहीं है लेकिन यह बहुत जरूरी है कि संबंधों में मिठास घोलने की प्रक्रिया जारी रहे। खासकर ऐसे दौर में जब चीन इस बात की हर संभव कोशिश कर रहा है कि नेपाल और भारत के संबंधों में खटास पैदा हो। रिश्ते बिगड़ें और नेपाल, चीन की गोद में खेलने पर मजबूर हो जाए। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चीन की चालबाजियों को बालेन शाह समझ रहे हैं?

इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि बालेन भले ही राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आए हैं लेकिन अपने देश की नब्ज को वे अच्छी तरह समझते हैं। राजनीति में उनका अनुभव भले ही बहुत ज्यादा नहीं हो लेकिन उन्होंने जिस तरह के संकेत दिए हैं, उससे साफ झलकता है कि उन्हें विश्व राजनीति की समझ है और किसी भी मंच पर सीधा संवाद करने से भी उन्हें कोई परहेज नहीं है।

अमेरिका यात्रा में उन्होंने जिस तरह से पर्यावरण के मुद्दे को उठाया था और हिमालय के इलाके में बदलती हुई परिस्थितियों के लिए दिग्गजों को दोषी ठहराया था, उससे स्पष्ट है कि वे किसी के दबाव में आकर चुप्पी साधने वालों में से नहीं हैं। जब नेपाल में भीषण बाढ़ आई तो शुरुआती दौर में बचाव कार्य के लिए विदेशी मदद को शुरु में इनकार किया



क्योंकि चीन ऐसा नहीं चाहता था।

लेकिन जब उन्हें लगा कि चीन का दबाव बर्दाश्त नहीं करना चाहिए तो अगले ही दिन उन्होंने अनुमति दे दी। ऐसे कई मौके आए हैं जब चीन की चाल में फंसने के बजाय बालेन ने अपनी समझ के अनुसार कार्य किया है। नेपाल में जब के।पी।शर्मा ओली या फिर प्रचंड प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब नेपाल की सत्ता में वही हो रहा था जो चीन चाह रहा था।

यही कारण है कि भारत के साथ नेपाल के संबंधों में खटास उत्पन्न हुई। इस खटास के लिए भारत को दोषी ठहराते हुए चीन के साथ प्रेम रखने वाले नेपाली नेताओं ने खूब प्रचार किया। वहां के युवाओं को यह समझाने की कोशिश की गई कि नेपाल को भारत पर्याप्त सम्मान नहीं देता है जबकि यह बात पूरी तरह गलत थी।

भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने बगैर किसी चाहत के नेपाल की हर मौके पर मदद की है। वास्तव में भारत ने नेपाल को खुद से अलग कभी समझा ही नहीं। यह बात सत्ता के स्तर पर भी रही है और दोनों देशों की जनता के बीच भी यही भाव रहा है। आज भी न जाने कितने नेपाली भारत में रह रहे हैं, रोजी-रोटी कमा रहे हैं और कोई भी उन्हें खुद से अलग करके नहीं देखता है। यदि आप भारत-नेपाल सीमा पर बसे गांवों में जाएं तो वहां रोटी-बेटी का व्यवहार है। सीमा के पास दोनों देशों में खूब शादियां होती हैं। दोनों देशों के बीच 1750 किलोमीटर से ज्यादा सीमा है और ज्यादातर हिस्सा खुला हुआ है। कभी इस पर कोई विवाद नहीं हुआ लेकिन चीन का प्रभाव वहां की सत्ता पर बढ़ा तो सीमा की कटुता भी पैदा होने लगी।

बालेन शाह जब सत्ता में आए तो उन्होंने भी सीमा पर कुछ बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की। मगर जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि इससे नेपाल का ही अहित हो रहा है। अब सख्ती में अघोषित ढील दी गई है। बालेन शाह को निश्चय ही समझ में आ रहा होगा कि ओली और प्रचंड के जमाने में चीन ने जो चालें चली हैं, उसका दुष्परिणाम नेपाल भुगत रहा है।

अभी बालेन जिस भैरवा, महेंद्रनगर और नेपालगंज में विमानों के संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र में प्रवेश का आग्रह कर रहे हैं उससे चीन किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। या तो एयरपोर्ट उसके ठेकेदारों ने बनाए हैं या फिर कुछ एयरपोर्ट का संचालन चीनी कंपनियां कर रही हैं। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो चीन ने ही बनाया है।

स्वाभाविक सी शंका पैदा हो सकती है कि यदि भारतीय क्षेत्र से नेपाल के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी गई तो सुरक्षा से कोई समझौता तो नहीं होगा। मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए यह जरूरी है। भारत ने हमेशा नेपाल के साथ सदाशयता बरती है इसलिए इस मसले को इसी नजरिये से देखा जाना चाहिए।

हालांकि यह जानकारी भी सामने आ रही है कि भारत ने नेपाल से कहा है कि वह आपात स्थिति में बागडोगरा हवाई अड्डे से नेपाली हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति दे। बागडोगरा चिकन नेक के पास है। यदि बांग्लादेश या चीन कोई खुराफात करते हैं तो भारत को उड़ान के लिए नेपाली क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। स्वाभाविक सी बात है कि चीन इस बात को कभी पसंद नहीं करेगा।

बालेन शाह से उम्मीद की जा रही है कि वे नेपाल को सुख और समृद्धि के रास्ते पर ले जाएंगे क्योंकि उनके पास दो तिहाई बहुमत है, उन्हें सत्ता जाने का डर नहीं सता रहा है इसलिए वे कठोर कदम भी उठा सकते हैं। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा लेकिन बालेन को भी यह बात ध्यान में रखनी होगी कि चीनी निवेश के लालच में वे कोई ऐसा कदम न उठाएं।

जिससे भारत की अस्मिता को कोई खतरा हो। ताली दोनों हाथों से बजती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत के साथ जो छोटे-मोटे मतभेद हैं, उन्हें दूर करने में वे चीन को अड़ंगा नहीं डालने देंगे। उन्हें समझना होगा कि चीनी निवेश किसी देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधारता बल्कि उसे अपने शिकंजे में कसता है। यदि वे यह समझ पाएं तो भारत और नेपाल दोनों मिलकर तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे।

इज़राइल पर राहुल गांधी की नेहरूवादी कूटनीति के मायने

दिलीप कुमार पाठक

विदेश नीति और जज़्बात के बीच की लकीर बहुत पतली होती है, और हर कोई इसे संभाल नहीं पाता। इज़राइल और ग़ाज़ा के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो रुख़ रखा है, उसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। वामपंथी दलों से लेकर कांग्रेस के अपने सहयोगियों तक, कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। मगर राजनीतिक, कूटनीतिक नज़रिए से देखें, तो यह एक सधे हुए और परिपक्व राजनेता का कदम दिखता है। ग़ाज़ा में मासूमों की मौत और तबाही की तस्वीरें देखकर किसी भी संवेदनशील इन्सान का मन कचोट जाता है। आम लोगों की भावनाएं वाजिब हैं। पर विदेश नीति सिर्फ़ नारों या भावनाओं से नहीं चलती। यहीं पर एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और एक ज़िम्मेदार राजनेता का फ़र्क दिखता है। एक्टिविस्ट सिर्फ़ अपने दिल और आदर्शों की सुनता है, उसे देश चलाने या कूटनीतिक रिश्ते संभालने की फ़िक्र नहीं होती। दूसरी तरफ़, भारत जैसे बड़े देश के नेता प्रतिपक्ष के कंधों पर देश के हितों, सुरक्षा और भविष्य की कूटनीति की ज़िम्मेदारी होती है। राहुल के भीतर मानवीयता की कोई कमी नहीं है। उन्होंने ग़ाज़ा में हो रहे जुल्म और निर्दोष लोगों की मौत की साफ़ निंदा करके इंसानियत का पक्ष मजबूती से रखा, पर यह भी समझदारी दिखाई कि विदेश नीति भावुकता के बजाय व्यावहारिक समझ से चलती है। राहुल के इस संतुलित रुख़ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की झलक साफ दिखती है, जहाँ आदर्शवाद और व्यावहारिक यथार्थवाद साथ चलते हैं। कई लोग मान लेते हैं कि नेहरू की नीति बस आदर्शों तक सिमटी थी, जबकि असलियत यह है कि उन्होंने दुनिया भर के अन्याय और मानवाधिकार हनन के ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाई, पर जब भारत की संप्रभुता और हितों की बात आई, तो हमेशा व्यावहारिक फ़ैसले लिए। 1947 में भारत ने फ़िलिस्तीन के बंटवारे का विरोध किया था, लेकिन जब इज़राइल हकीकत बन गया, तो 1950 में नेहरू सरकार ने उसे एक देश के तौर पर मान्यता दी। 1954 में नेहरू जी ने साफ़ कहा था कि वे ऐसे किसी प्रस्ताव के साथ नहीं होंगे जो इज़राइल के वज़ूद को अंतरराष्ट्रीय क़ानून के ख़िलाफ़ माने। 1962 के चीन युद्ध और 1965 के पाकिस्तान युद्ध के वक़्त भारत ने इज़राइल से रक्षा सामग्री भी ली थी। इससे यह बात पक्की होती है कि पीड़ितों के साथ खड़े होना और अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी साझेदारी करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं, जिन्हें साथ लेकर चलना पड़ता है। घरेलू राजनीति में कई बार इज़राइल और पाकिस्तान की तुलना कर दी जाती है, जो हमारे संदर्भ में पूरी तरह बेमानी है। पाकिस्तान के साथ हमारा सीधा सीमा विवाद और सीमा पार से आतंकवाद का टकराव है। इसके उलट, इज़राइल बरसों से भारत का भरोसेमंद रक्षा, कृषि और तकनीक साझेदार रहा है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान जब कई बड़े देश हिचकिचा रहे थे, तब इज़राइल ने ज़रूरी रक्षा उपकरण और तकनीक देकर भारत की बड़ी मदद की थी। इस ज़मीनी सच्चाई को अनदेखा करके कोई भी ज़िम्मेदार नेता विदेश नीति पर बात नहीं कर सकता। दूसरी ओर, इस पूरे मामले का एक आलोचनात्मक पक्ष भी है, जिसे वामपंथी दल और मानवाधिकार से जुड़े लोग लगातार उठा रहे हैं।

जहां कभी तबाही मचाई थी चट्टानों ने वहीं आज उभरी आस्था, जानें 31 दिव्य आकृतियों का रहस्य



2013 में केदारनाथ यात्री पर आई भीषण जलप्रलय ने पूरे देश को हिला दिया था। उस दौरान पहाड़ टूटे, विशाल चट्टानें खिसकर मंदिर के पास आकर रुक गईं और हजारों लोगों की जान बचाने में ढाल बनीं। आज वही चट्टानें एक नए आस्था केंद्र के रूप में लोगों का ध्यान खींच रही हैं।

चट्टानों पर दिखीं 31 रहस्यमयी आकृतियां

स्थानीय लोगों, पुजारियों और कई विशेषज्ञों के अनुसार, इन चट्टानों की सतह पर करीब 31 अलग-अलग आकृतियां उभरकर दिखाई दे रही हैं। इनमें भगवान शिव से मिलती-जुलती आकृतियां, नंदी के जैसे आकार, साधु-संतों की आकृतियां और कुछ ऐसी रेखाएं शामिल हैं, जिन्हें श्रद्धालु प्राकृतिक मूर्ति परिवार जैसा मानने लगे हैं।

क्या यह प्रकृति का चमत्कार या दिव्य संकेत?

अब तक वैज्ञानिक रूप से यह साफ नहीं हो पाया है कि ऐसी विशाल और गहरी आकृतियां चट्टानों पर कैसे बनीं। कुछ विशेषज्ञ इन्हें प्राकृतिक भू-आकृतिक संरचना बताते हैं, जबकि कई श्रद्धालु इसे शिव की शक्तियों और दिव्य संकेत मान रहे हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है- '2013 की आपदा के बाद भी मंदिर सुरक्षित रहा... अब इन चट्टानों में शिव के रूप दिखना कोई साधारण बात नहीं है।'

तीर्थयात्रियों के लिए नया आकर्षण

इन चट्टानों को देखने के लिए अब केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। लोग इन्हें आस्था का प्रतीक, चमत्कार का संकेत, प्रकृति की अद्भुत कला और शिव की कृपा मानकर प्रति दिन बड़ी संख्या में दर्शन करने आ रहे हैं।

रहस्य और श्रद्धा बढ़ाती अनोखी कहानी

चाहे ये आकृतियां संयोग हों या प्रकृति के अद्भुत खेल— केदारनाथ की ये चट्टानें अब एक नई आध्यात्मिक कहानी बन चुकी हैं। 2013 की आपदा के दौरान मंदिर को बचाने वाली ये चट्टानें आज श्रद्धालुओं की आस्था का नया केंद्र बनकर उभर रही हैं। यह घटना बताती है कि प्रकृति और आस्था जब मिलती हैं, तो इतिहास खुद-ब-खुद नई कहानी रच देता है।

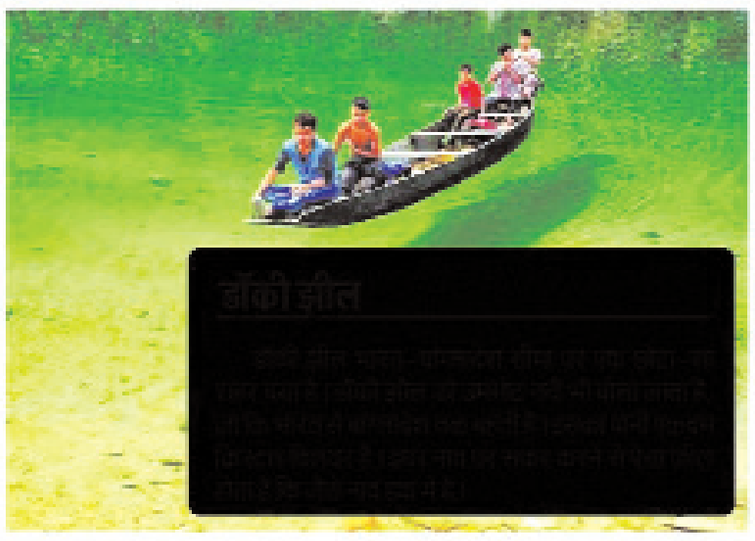


बादलों का घर मेघालय : इन 5 जगहों की सैर आपको जीवन भर याद रहेगी, बनाएं ट्रिप का प्लान!



नॉर्थ-ईस्ट राज्य प्राकृतिक और सुंदर वादियों के लिए जाना जाता है। अगर आप मेघालय जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है। मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। यहां की खूबसूरती दुनियाभर में मशहूर है। मेघालय में पानी भी शीशे की तरह चमकता है और यहां की सुंदरता देखकर आप कहीं न कहीं खो जाएंगे। जो एक बार मेघालय घूमने जाएगा वो वहीं का होकर रह गया है। मेघालय में आपको पहाड़, झरने, नदियां, झील, हरे जंगल खूबसूरत देखने को मिलेगा। अगर आपको कहीं है आप किन जगहों पर जरूर घूमने जाएं।

शिलॉन्ग



मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग घूमने जरूर जाएं। यह शहर बेहद ही खूबसूरत और हरियाली से भरा हुआ है। मेघालय पूरी हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ है शिलॉन्ग। इसे मिनी स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। शिलॉन्ग में आप व्यू पॉइंट, लेडकोर पीक, स्पेशल झील फॉल्स, लेडी हैदरी पार्क और एलिफेंट फॉल्स को जरूर देखें।

दावकी

अगर आप मेघालय आ रहे है, तो पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में स्थित दावकी छोटा सा टाउन है, यहां पर घूमने के लिए कई सारी जगहें हैं। इसपर आपको सुंदर झरने देखने को मिलेंगे। दावकी में जयंतिया पहाड़ियों से बहने वाली दावकी नदी बहती है। यह नदी अपने क्रिस्टल-क्लियर पानी के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। दावकी में आप इंडो-बांग्लादेश बॉर्डर भी देख सकते हैं।

मौसिनराम

मेघालय के खासी हिल्स में मौसिनराम एक सुंदर बस्ती है, यह अपनी प्राकृतिक स्टैलेग्माइट शिवलिंग नुमा संरचनाओं के लिए जाना जाता है। यहां पर मानसिनमुडा गुफा देखने को लायक मिलती है। इस गुफा में शिवलिंग भी बनी है, जो कि स्टैलेग्माइट के लिए जानी जाती है। यहां का वातावरण एकदम शांत और सुकून से भरा हुआ है। कलकल करता हुआ पानी की आवाज आपके मन को शांति पहुंचाने करेगा।

मावफलांग पवित्र वन

मेघालय में मावफलांग का एक प्रसिद्ध जंगल है, जो काफी शुद्ध व पवित्र माना जाता है। इस जंगल से एक भी पत्ती बाहर लेकर जाना मना है और इस जंगल में आपको रुद्राक्ष के पेड़ मिलेंगे, इस मुख्य वजह से यहां होती है।

मेघालय, जिसे 'बादलों का घर' कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और क्रिस्टल-क्लियर नदियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ शिलॉन्ग, डॉकी झील, दावकी, मौरिनराम और मावफलांग पवित्र वन जैसी मनोरम जगहें आपके मन को मोह लेंगी।

जापलांग लोरी पॉइंट, बुरकिल झरने, मालस्या-लिंग, रिनाई जैसी खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकती है।

खूबसूरती और रोमांच का अनोखा संगम, हिमाचल का 'कौमिक' गांव, जहां चांदनी रातें बिखेरती हैं जादू

उत्तराखंड में ऐसी कई अद्भुत और शानदार जगहें मौजूद हैं, जहां पर घूमने के लिए हर मौसम में विश्व के हर कोने से पर्यटक पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौमिक एक ऐसा गांव है, जिसकी खूबसूरती देखकर हर कोई अद्भुत स्थानों की दुनिया में चला जाएगा।

हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमाचल के स्पिति में स्थित एक विशेष प्रतिबंधित पर्यटन स्थल है। इसको अक्सर लोग तिब्बत की "देव भूमि" के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जो 'बर्फीले पहाड़ों के प्रांत' के नाम से फेमस है। उत्तराखंड में ऐसी कई अद्भुत और शानदार जगहें मौजूद हैं, जहां पर घूमने के लिए हर मौसम में विश्व के हर कोने से पर्यटक पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौमिक एक ऐसा गांव है, जिसकी खूबसूरती देखकर हर कोई अद्भुत स्थानों की दुनिया में चला जाएगा। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कौमिक की खासियत और इसके आसपास खूबसूरत जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

कौमिक गांव

कौमिक गांव को कई लोग कौमिक के नाम से भी जानते हैं। यह गांव खूबसूरत और मनमोहक गांव हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है।

कौमिक गांव हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 444 किमी दूर है। इसके साथ ही कौमिक गांव मनाली से 202, कुल्लू से 224 और किन्नौर पिओ से करीब 228 किमी दूर है।

कौमिक गांव की खासियत

हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले की स्पीति में स्थित कौमिक गांव काफी ज्यादा खूबसूरत है। कौमिक गांव को भारत के अलावा दुनिया के सबसे गांव होने की प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है।

कौमिक गांव समुद्र तल से करीब 15 हजार फीट की ऊंचाई पर मौजूद कौमिक गांव ढोक-ढोक ऊंचे पहाड़, किस्टल से अधिक साफ झील-झरनों का पानी और नीले आसमान के लिए जाना जाता है। कौमिक गांव की चांदनी रात पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करती है। यहां का शांत और शुद्ध वातावरण भी पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। इसलिए इस गांव को हिमाचल प्रदेश का हरीतिम जन्नत माना जाता है।

लुंडुप त्सोमो गोम्पा बौद्ध मठ

कौमिक गांव अपनी खूबसूरती के अलावा लुंडुप त्सोमो गोम्पा बौद्ध मठ के लिए भी आकर्षण का केंद्र माना जाता है। इस मठ के बारे में बताया जाता है कि इसका इतिहास करीब 500 साल से भी अधिक पुराना है।

पहाड़ी की चोटी पर मौजूद होने के कारण लुंडुप त्सोमो गोम्पा बौद्ध मठ को एक्सप्लोर करना थोड़ा। लोगों का मानना होता है। मठ की ऊंचाई से कौमिक गांव के आसपास के लुभावने और हसीन दृश्यों को आखों में कैद कर सकते है। आप चाहे तो यहां पर खास फोटोशूटी भी कर सकते हैं।

एडवेंचर प्रेमियों के लिए स्वर्ग

यह गांव सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि गोम्पा बौद्ध मठ और एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग माना जाता है। यह गांव विंटर सीजन में सबसे अच्छे ट्रेकिंग और स्नोकिंग के लिए फेमस है।

सर्दियों के मौसम के अलावा आप यहां पर गर्मियों में भी आ सकते हैं। यहां पर हजारों लोग ट्रेकिंग, साइकल राइडिंग और कैंपिंग के लिए भी आते हैं। आप यहां पर बॉक बनाइंग का भी लुफ्त उठा सकते है।

ऐसे पहुंचे कौमिक गांव

बता दें कि इस गांव पहुंचना बेहद आसान है। इसके लिए आप दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से बस लेकर स्पीति घाटी पहुंच सकते हैं। दिल्ली कश्मीरी गेट से स्पीति घाटी के लिए बस चलती है। स्पीति घाटी पहुंचने के बाद आप वाहक रेट पर लेकर कौमिक गांव पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप शिमला से भी बस लेकर कौमिक गांव पहुंच सकते है।

ये कैसा झरना जो बहता है उल्टा! नीचे गिरने की बजाए ऊपर चढ़ता है पानी, देखकर हिल जाएगा दिमाग



भारत में प्रकृति के कई ऐसे चमत्कार है, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इन्हीं में से एक है महाराष्ट्र का नानेघाट वाटरफॉल, जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देता है। आमतौर पर झरने ऊपर से नीचे गिरते है, लेकिन यह झरना नीचे से ऊपर बहता दिखाई देता है। इस अनोखे नजारे को देखने के लिए हर साल भारी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते है।

कहां स्थित है यह अनोखा झरना?

यह अनोखा झरना नानेघाट वाटरफॉल के नाम से मशहूर है और कोंकण समुद्र तट तथा जुन्नार नगर के बीच स्थित है। मुंबई से इसकी दूरी करीब 120 किमी और पुणे से लगभग 150 किमी है। नाना घाट और 'रिवर्स वाटरफॉल' के नाम से जाना जाने वाला यह स्थान अपने अनोखे प्राकृतिक दृश्य के कारण पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है।

क्यों बहता है यह झरना उल्टी दिशा में?

गुरुत्वाकर्षण के नियम के मुताबिक हर चीज ऊपर से नीचे की ओर आती है, लेकिन नानेघाट का यह झरना तेज हवाओं के कारण ठीक उल्टा व्यवहार करता है। यहां हवा इतनी तेज चलती है कि नीचे गिरता पानी हवा का दबाव पकड़कर ऊपर उड़ने लगता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसी तेज हवा की दिशा और गति के कारण यह झरना उल्टी दिशा में बहता दिखाई देता है, जो इसे बेहद रहस्यमयी और अनोखा बनाता है।

इसे देखने पर क्या महसूस होता है?

जो भी इस झरने को पहली बार देखता है, वह दंग रह जाता है। दूर से ऐसा लगता है मानो पानी सीधी पहाड़ी की तरफ ऊपर बह रहा हो। यह अद्भुत नजारा लोगों को कुछ पल के लिए स्तब्ध कर देता है, क्योंकि प्रकृति का ऐसा उल्टा नजारा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता।

कैसे पहुंचे नानेघाट रिवर्स वाटरफॉल?

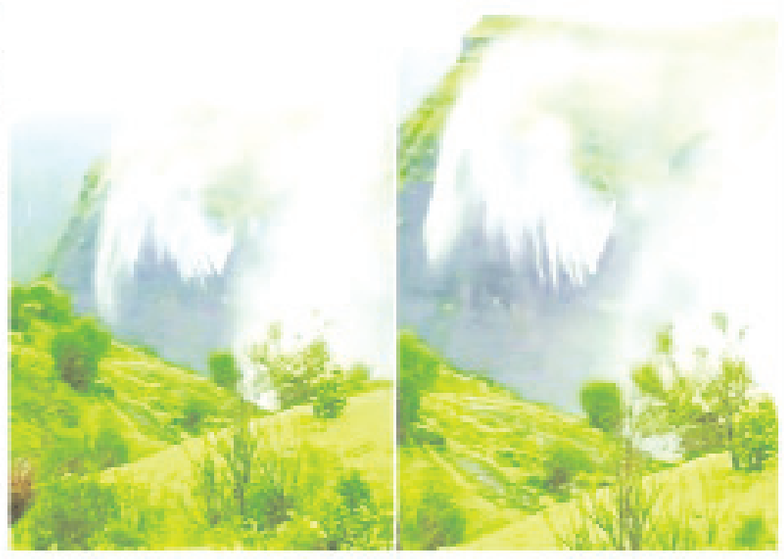
अगर आप नानेघाट रिवर्स वाटरफॉल देखने का प्लान बना रहे है, तो यहां पहुंचना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको कल्याण बस स्टैंड जाना होगा, जहां से जुन्नार और नानेघाट के लिए नियमित बसें मिल जाती है। चाहे तो आप सड़क मार्ग से भी अपनी कार या टैक्सी से आराम से नानेघाट पहुंच सकते हैं। यहां तक पहुंचने का रास्ता सुंदर घाटी और हरियाली से भरा है, जो यात्रा को और भी खास बनाता है।

ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग

नानेघाट ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह ट्रेल सह्याद्रि के घने जंगल क्षेत्र का हिस्सा है और रोमांच से भरपूर प्राकृतिक रास्तों से होकर गुजरता है। कल्याण-अहमदनगर हाईवे से शुरू होने वाला यह ट्रेकिंग रूट खासतौर पर यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि यहां का शांत वातावरण, पहाड़ी दृश्य और हल्की हवाएं पूरे सफर को यादगार बना देती है।

घूमने का सबसे अच्छा समय

नानेघाट रिवर्स वाटरफॉल को देखने का सबसे अच्छा समय मानसून का मौसम माना जाता है। जुलाई से सितंबर के बीच यहां की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। इस दौरान हवाएं बेहद तेज चलती है, जिसकी वजह से झरना सबसे मनमोहक तरीके से उल्टी दिशा में बहता दिखाई देता है। यही समय इस अनोखे प्राकृतिक चमत्कार को नजदीक से देखने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है।



राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

संवैधानिक सत्ता का सबसे बड़ा अपमान : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को इंडिया गठबंधन और तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मदुरै की तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित विवादित दीपथून पत्थर के खंभे पर कार्तिगई दीपम के तहत एक बार प्रतीकात्मक रूप से दीपक जलाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए त्रिवेदी ने कहा, आज मैं आपका ध्यान उस बात की ओर खींचना चाहता हूं, जिसे हम इंडिया गठबंधन और तमिलनाडु सरकार की ओर से किया गया सबसे बड़ा संवैधानिक उल्लंघन मानते हैं। मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें कुछ शर्तों के साथ केवल एक दिन के लिए कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न तो माना और न ही लागू किया।



सपा के लिए अब राम नाम सत्य का समय : योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर एक साथ तीखा हमला बोलते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमा दिया है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि दो नावों की सवारी करने वाले डूबते हैं। अखिलेश को अयोध्या जाने से पहले रामभक्तों और हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि राधे-राधे तो शुरुआत है, सपा के लिए अब राम नाम सत्य का समय आ रहा है। मथुरा में राधे-राधे, अयोध्या में जय श्रीराम और काशी में हर-हर महादेव कहना आस्था के अनुरूप है, जबकि राम नाम सत्य विदाई के समय कहा जाता है। मुख्यमंत्री बुधवार को एक टीवी मीडिया समूह को दिए साक्षात्कार में बोल रहे थे। योगी ने सपा की राजनीति को परिवार तक सीमित बताते हुए उसके पीडीए की नई व्याख्या की। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है।



हम भिखारी नहीं हैं जो सपा की खैरात का इंतजार करें : इमरान

नईदिल्ली। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच सीट-बंटवारे की बातचीत में एक और रुकावट आ गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी किए जाने पर तीखा हमला बोला है। मसूद ने इस क्षेत्रीय पार्टी पर आरोप लगाया कि जब बातचीत अभी चल ही रही है, तब उसने एकतरफा फैसले ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोई भिखारियों की पार्टी नहीं है जो अखिलेश यादव से कुछ मिलने का इंतज़ार करे। मसूद ने यह भी सवाल उठाया कि क्या समाजवादी पार्टी इस गठबंधन को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि उनकी राजनीतिक लड़ाई भाजपा के खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ। उनके इन बयानों ने इंडिया गठबंधन के इन दोनों सहयोगियों के बीच के मतभेदों को और उजागर कर दिया है, जबकि वे विधानसभा चुनावों के लिए सीट-बंटवारे पर बातचीत कर रहे हैं।



अखिलेश यादव ने 5 उम्मीदवार उतारकर इमरान को दिया झटका

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए चल रही सीट-बंटवारे की बातचीत के बीच, समाजवादी पार्टी (सपा) पर कांग्रेस को धोखा देने का आरोप लगाया है। 25 नवंबर को बोलते हुए, राजभर ने दावा किया कि सपा ने जानबूझकर पांच उम्मीदवारों की घोषणा की, ताकि अपने गठबंधन सहयोगी पर दबाव बनाया जा सके और मुस्लिम वोटों को चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन की ओर जाने से रोका जा सके। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का पालन नहीं किया और कांग्रेस को धोखा दिया। समाजवादी पार्टी द्वारा 5 सीटों की सूची जारी करने से हमारे सामने दो बातें साफ हो गईं- कांग्रेस पर दबाव बनाना, और चंद्रशेखर आज़ाद जी तथा ओवैसी जी के गठबंधन को रोकना। मुस्लिम वोटों को ओवैसी जी के साथ जाने से रोकने के लिए, आपने 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की और पीडीए को परिभाषित किया।



सपा-कांग्रेस गठबंधन बेमेल शादी जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी

लखनऊ। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सीट-बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच बढ़ते मतभेदों के बीच, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को उनके गठबंधन को बेमेल शादी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दलों के बीच हमेशा से कड़वाहट और दुश्मनी रही है। पत्रकारों से बातचीत में ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा-कांग्रेस का गठबंधन एक बेमेल शादी की तरह है, जिसमें दोनों दलों के बीच कड़वाहट और दुश्मनी है। उनके कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर इस गठबंधन को सही नहीं ठहरा सकते और उत्तर प्रदेश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को बढ़ावा देती है, जबकि कांग्रेस भ्रष्टाचार और लोकतंत्र-विरोधी तौर-तरीकों से जुड़ी है। कांग्रेस ने देश में आपातकाल (इमरजेंसी) थोपा था, और ये दोनों दल देश और राज्य को अपनी निजी जागीर की तरह चलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस गठबंधन को कभी स्वीकार नहीं करेगी, और अंतत: यह गठबंधन विफल हो जाएगा।



केशव प्रसाद का सपा-कांग्रेस पर वार, बोले-

यूपी में तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार : मौर्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के गठबंधन को 'ठगबंधन' करार देते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि ये दोनों दल अपराधियों, दंगाइयों और भ्रष्ट तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मौर्य ने साथ ही दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मौर्य ने यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान विपक्षी गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''यह कोई गठबंधन नहीं बल्कि गुंडों, अपराधियों, भ्रष्ट लोगों और दंगाइयों का 'ठगबंधन' है। इसकी हालत न तो आज अच्छी है और न ही भविष्य में सुधरने वाली है।''

कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के बीच सपा द्वारा पांच उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने के बारे में पूछे जाने पर मौर्य ने कहा कि यह दोनों विपक्षी दलों की अंदरूनी समस्याओं को दर्शाता है और इसका भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, ''दोनों दलों (सपा और कांग्रेस) के बीच इस तरह की नौटंकी होती रहती है लेकिन इससे भाजपा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।'' कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सपा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ। उनके इस बयान पर मौर्य ने कहा, ''अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो उन्हें राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए।'' उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है और वह ''भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।'' उन्होंने कहा, ''समाजवादी पार्टी को वोट देना मुसीबत को न्योता देने जैसा है, जबकि कांग्रेस को वोट देना देश को फिर से पतन की ओर ले जाना होगा। जनता भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी है और पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।''



मौर्य ने दावा किया कि सपा और कांग्रेस चाहे मिलकर चुनाव लड़ें या अलग-अलग, जीत भाजपा की ही होगी। उन्होंने कहा, ''इस 'ठगबंधन' का कोई भी व्यक्ति भाजपा के कमल को खिलने से नहीं रोक सकता।'' मौर्य ने सपा की ओर से घोषित पांच उम्मीदवारों में से तीन मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारे जाने पर निशाना साधा और पार्टी पर ''मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति'' करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा उत्तर प्रदेश में फिर से दंगों का दौर और अपराधियों एवं माफियाओं का वर्चस्व लौटाना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि राज्य ''पिछले 10 वर्ष से दंगामुक्त'' रहा है। मौर्य ने कहा, ''कमल का बटन दबाने से उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहेगा। अगर लोग साइकिल का बटन दबाते हैं तो गुंडे, अपराधी और माफिया तत्व उनका शोषण करेंगे, उनकी जमीन हड़प लेंगे और उनकी बेटियों एवं महिलाओं को परेशान करेंगे।'' उन्होंने मतदाताओं से सपा, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को हराने तथा भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की जीत सुनिश्चित करने की अपील की।

संविधान दिवस पर कांग्रेस का आज देशव्यापी मार्च

एसआईआर के विरोध में होगी रैली

नई दिल्ली। संविधान की रक्षा के लिए चलाए जा रहे अपने अभियान के तहत, कांग्रेस 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर संविधान रक्षा मार्च आयोजित करेगी। यह जानकारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता लखनऊ में एक रैली करेंगे, जो 2027 में होने वाले राज्य चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण संदेश देगी।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि हर प्रदेश कांग्रेस समिति (पीसीसी) अपने-अपने राज्य में यह मार्च आयोजित करेगी, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 26 नवंबर को लखनऊ में होने वाले मार्च में शामिल होंगे।

हर मार्च की शुरुआत बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर या महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास से होगी, जो संविधान की रक्षा के प्रति कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्र निर्माताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद, कांग्रेस कार्यकर्ता और नागरिक मिलकर संविधान की प्रस्तावना (प्रिएम्बल) पढ़ेंगे। इस दौरान वे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को याद करेंगे और संविधान की रक्षा करने की शपथ लेंगे।

इन मार्चों के साथ-साथ, कांग्रेस कार्यकर्ता वोट रक्षक अभियान के तहत हर मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ) तक पहुंचेंगे। वे उन मतदाताओं की पहचान करेंगे जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, और उन्हें अपना वोट देने का अधिकार वापस पाने में मदद करेंगे।

वेणुगोपाल ने संविधान को मानने वाले सभी नागरिकों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में इन मार्चों में हिस्सा लें और 26 नवंबर को संकल्प के एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाएं। उन्होंने कहा, संविधान ने हर भारतीय को वोट का अधिकार दिया है।



भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसा करना उसका कर्तव्य है। मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों पर चिंता जताते हुए, वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के दस्तावेजी सबूत देश के सामने रखे हैं।

उन्होंने महादेपुरा में फर्जी और डुप्लिकेट प्रविष्टियों, अलंद में हजारों असली मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाने की कोशिशों, और हरियाणा तथा अन्य राज्यों में हुई गंभीर अनियमितताओं का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये घटनाएं मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर और सुनियोजित तरीके से की गई छेड़छाड़ की ओर इशारा करती हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि निष्पक्ष जांच का आदेश देने के बजाय, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने निष्कर्षों को खारिज कर दिया, विपक्ष के नेता से हलफनामे मांगे और जांच एजेंसियों द्वारा मांगी गई जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। वेणुगोपाल ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का भी जिक्र किया, जो बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू हुआ था। इसके दूसरे चरण में यह प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैल गई, और तीसरे चरण में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच गई।

उन्होंने कहा कि हालांकि इस कवायद का घोषित उद्देश्य मतदाता सूचियों को त्रुटिहीन बनाना था, लेकिन इसका असर यह हुआ कि नागरिकों को ही यह साबित करना पड़ा कि वे यहीं के निवासी हैं।

बयान में कहा गया है, केवल बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से ही 65 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए, और तीनों चरणों को मिलाकर अब माना जा रहा है कि हटाए गए नामों की संख्या 13 करोड़ से अधिक हो गई है। बयान में आगे कहा गया है कि इस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, प्रवासी मजदूर और वे महिलाएं हैं जिन्होंने शादी के बाद अपना घर बदल लिया है। ये वही नागरिक हैं जिन्हें सशक्त बनाने के लिए बाबासाहेब और गांधीजी ने संघर्ष किया था।

वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता प्रभावित हुई है। संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए, वेणुगोपाल ने कहा कि इसमें निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो तत्कालीन सरकार के प्रभाव से मुक्त है।

हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि कानून में संशोधन करके चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया, जिससे मौजूदा सरकार को उनकी नियुक्तियों में निर्णायक अधिकार मिल गया। बयान में कहा गया, एक और संशोधन के जरिए चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए कार्यों के लिए आजीवन कानूनी सुरक्षा (इम्युनिटी) दे दी गई। इससे उन्हें संवैधानिक मर्यादा और सिद्धांतों का उल्लंघन करने की पूरी छूट मिल गई है।

बयान में आगे कहा गया, जब किसी नागरिक का वोट चुरा लिया जाता है, तो संविधान द्वारा दिए गए बाकी सभी अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। इसलिए, यह लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि क्या भारत हम, भारत के लोगों का लोकतंत्र बना रहेगा या नहीं।

संविधान दिवस पर आज घोषणा पत्र जारी करेगी सपा

लखनऊ। समाजवादी पार्टी कल 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर यूपी चुनाव 2027 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इसे जन-मन का मैनिफेस्टो नाम दिया गया है। इसके साथ सत्ताईस का संकल्प: पीडीए का प्रणपत्र का नारा जोड़ा गया है। बीते दिनों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेसवार्ता में कहा था कि सपा के घोषणा पत्र में महिला, युवा और पीडीए पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा।



पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन की देखरेख में तैयार किए जा रहे इस घोषणापत्र के ज़रिए सपा संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण की रक्षा को अपने अभियान के केंद्र में रखते हुए पीडीए महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के लिए रोजगार, शिक्षा व सामाजिक न्याय से जुड़े वादे पेश करेगी, जिसके बाद अलग-अलग मंडलों और जिलों के लिए क्षेत्रीय घोषणापत्र भी लाए जाने की योजना है।

चुनाव से काफी पहले इसे जारी करने का मकसद पार्टी को जमीनी स्तर पर जनता के बीच अपने मुद्दों को पहुंचाने के लिए पर्याप्त समय देना है, जबकि विस्तृत योजनाओं का खुलासा 26 नवंबर के लॉन्च के साथ ही होगा।

26 नवंबर को समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय में पीडीए घोषणा पत्र लॉन्च करेगी। इस कार्यक्रम के बाद संविधान मार्च का आयोजन किया जाएगा जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल होंगे। मार्च नेहरू भवन स्थित गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुरू होगा। एनेक्सी होते हुए हजरतगंज स्थित बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ इसका समापन होगा। इसमें राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी, पूर्व सांसद पीएल पुनिया और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम संयोजक सांसद तनुज पुनिया ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेशभर के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत के लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल की राह हुई मुश्किल

मुम्बई। भारतीय टीम के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 की राह बेहद कठिन हो गयी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के ड्रॉ होने बाद अब भारतीय टीम अपने बचे हुए सभी मैच जीत भी ले तो भी उसका फाइनल में पहुंचना अन्य टीमों के परिणामों पर निर्भर करेगा। अब एक भी हार टीम को दौड़ से बाहर कर देगी। वहीं जीत के बाद भी उनकी जगह पक्की नहीं रहेगी। भारत के पास अब केवल छह टेस्ट मैच शेष हैं। इनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर पांच मुकाबले शामिल हैं। इन सभी में जीत के बाद भी उसका अंक प्रतिशत (पीसीटी) अधिकतम 66.67 तक ही पहुंच पाएगा। इस प्राकार उसे शीर्ष-2 में जगह बनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के परिणामों पर नजर रखनी होगी। ऐसे में भारतीय टीम को अपने शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ दूसरी टीमों के परिणाम अपने अनुकूल चाहिये होंगे। अभी अंक तालिका में दक्षिण अफ्रीका 8 मैचों में 6 जीत के साथ शीर्ष पर है और फाइनल की सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है। उसके छह मुकाबले बाकी हैं, जिनमें बांग्लादेश, इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज शामिल हैं। वहीं भारत के साथ टेस्ट ड्रॉ के बाद न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर खिसक गया है, जिसके पास अभी नौ टेस्ट मैच खेलने हैं, जिनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी नौ मैच खेलने हैं, जिसमें भारत के खिलाफ विदेश में होने वाली महत्वपूर्ण सीरीज भी शामिल है। इन सभी टीमों का प्रदर्शन भारत की संभावनाओं पर प्रभाव डालेगा। भारत के लिए फाइनल में पहुंचने का एक ही रास्ता है और वह है अपने सभी छह टेस्ट मैच बड़े अंतर से जीतना। इसमें खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में 5-0 की क्लीन स्वीप करना उसके लिए निर्णायक साबित हो सकता है।



आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स ने लगाई 1,502 अंकों की छलांग, निफ्टी 25,819 पर

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1,502.29 अंकों की तेजी के साथ 83,938.28 पर पहुंच गया। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 भी 469.60 अंकों की तेजी के साथ 25,819.25 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 2,062.22 अंकों की छलांग लगाई और निफ्टी 602 अंक चढ़ा। बाजार में आई इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में करीब 6.50 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 3% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में भी 4% तक की तेजी देखने को मिली। इन कंपनियों का निफ्टी में बड़ा वेटेज होने के कारण इनके शेयरों में खरीदारी से इंडेक्स को मजबूत सहारा मिला। अमेरिकी बाजार में एनवीडिया,एएमडी और माइक्रो जैसे एआई से जुड़े शेयरों में गिरावट देखने को मिली।

भारत का ई-कॉमर्स निर्यात 2,700 करोड़ डॉलर पहुंचा

नई दिल्ली। ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमेजन के अमेजन ग्लोबल सेलिंग कार्यक्रम के तहत भारत से कुल निर्यात 2,700 करोड़ अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। इस मंच पर निर्यातकों की संख्या एक साल में 20 प्रतिशत बढ़कर 2.4 लाख हो गई है। कंपनी ने बयान में कहा कि यह उपलब्धि 2030 तक भारत से कुल आठ लाख करोड़ डॉलर का ई-कॉमर्स निर्यात संभव बनाने के उसके लक्ष्य की दिशा में प्रगति को दर्शाती है। वर्ष 2015 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत भारत में बने एक अरब से अधिक उत्पाद अमेजन के वैश्विक बाजारों के ग्राहकों को बेचे जा चुके हैं। कंपनी के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत 36,000 से अधिक निर्यातकों के साथ दिल्ली राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पहले स्थान पर है। इसके बाद राजस्थान (32,500 से अधिक)का स्थान है।

भारत और चीन पर फिर टैरिफ बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत, चीन समेत कई देशों में टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जेमिसन ग्रीर इसी हफ्ते विदेशी औद्योगिक सब्सिडी की जांच के नतीजे घोषित कर सकते हैं। इसमें चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए जाने की संभावना है। मार्च में, यूएसटीआर ने 16 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ जांच शुरू की थी। चिंता यह थी कि सरकारी सब्सिडी के कारण विदेशी निर्माताओं को अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले अनुचित लाभ मिल रहा है। ये जांच ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत की गई थीं। यह कानून अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को उन देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने या अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जो अनुचित व्यापार प्रथाओं का इस्तेमाल करते पाए जाते हैं।

एनबीएफसी की स्थिति स्थिर रहने की उम्मीद: फिच

नई दिल्ली। मजबूत आर्थिक वृद्धि और अनुकूल नीतियों के कारण भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का कारोबारी माहौल स्थिर रहने की उम्मीद है। इससे कर्ज की मांग बनी रहेगी और कंपनियों को धन जुटाने की ऊंची लागत के दबाव से राहत मिलेगी। फिच रेटिंग्स ने बुधवार को यह बात कही। फिच ने अनुमान जताया कि महंगाई और ब्याज दरों में मामूली वृद्धि तथा वैश्विक आर्थिक वृद्धि की धीमी रफ्तार के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि दर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे ऊंची दरों में शामिल रहेगी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने सितंबर में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था।

भाषण बनाम भरोसा: वाटरलू संवाद में छिपा अर्थव्यवस्था का बड़ा राज!

अभिनय आकाश

सरकार ने टैक्स घटाया और कारोबार को आसान बनाया, लेकिन कंपनियों ने उसका फायदा जो है अपने यहां काम कर रहे वर्कर्स तक नहीं पहुंचाया, उनको बेनिफिट नहीं दिया। 19 नवंबर का दिन था जब प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत पर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज पर तीखा हमला बोला। देश के शीर्ष उद्योगपतियों के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में जो तल्खी, हताशा और एक तरह की बेबसी झलक रही थी, उसने आर्थिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। उनका अंदाज़ कुछ ऐसा था मानो वे कॉर्पोरेट जगत से सीधे पूछ रहे हों कि आखिर आपको आगे बढ़ने और निवेश करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? यह महज़ दिल की पुकार से कहीं अधिक गंभीर बात थी। यह स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कोई सेनापति अपने सैनिकों से मोर्चे पर आगे बढ़कर पहाड़ी पर चढ़ाई करने का आह्वान करे, लेकिन सैनिक अपनी जगह से टस से मस न हों, चाहे सेनापति उन्हें कितना ही क्यों न ललकारे। इस स्थिति को समझने के लिए 1970 की मशहूर फिल्म वाटरलू का एक संवाद बेहद सटीक बैठता है। फिल्म में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का किरदार निभा रहे क्रिस्टोफर प्लमर, डचेस ऑफ रिचमंड से कहते हैं, कौन जानना चाहेगा कि सैनिकों को लड़ने का जोश कहाँ से मिलता है? जिन (शराब) ही उनके देशभक्ति के जुनून का असली स्रोत है। बेशक, प्रधानमंत्री का इरादा कॉर्पोरेट इंडिया को उन कठोर शब्दों से नवाज़ने का कतई नहीं था जो वेलिंगटन ने अपने सैनिकों के लिए इस्तेमाल किए थे, लेकिन उनकी हताशा की गहराई कुछ वैसी ही महसूस हो रही है।

सवाल यह है कि कोई सरकार उद्योगपतियों को आगे बढ़ने के लिए किस तरह का जोश या टॉनिक दे सकती है? इसका जवाब है उद्यमिता को बढ़ावा देना। इसमें



नियमों में ढील, मिनिमम गवर्नमेंट, बाज़ार की निष्पक्ष निगरानी, वित्तीय अनुशासन और लाइसेंसिंग व निवेश की पाबंदियों से आज़ादी जैसे कदम शामिल हैं। यदि हम वेलिंगटन वाले जिन के उदाहरण को यहाँ लागू करें, तो इस प्रोत्साहन पैकेज का सबसे बड़ा और असरदार हिस्सा है, टैक्स में भारी कटौती। प्रधानमंत्री की नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार द्वारा दी गई इन तमाम रियायतों और बढ़ते कॉर्पोरेट मुनाफे के बावजूद, उद्योग जगत इसका लाभ आम लोगों और अर्थव्यवस्था तक नहीं पहुँचा रहा है। न तो उस अनुपात में कर्मचारियों का वेतन बढ़ रहा है, न नई भर्तियाँ हो रही हैं, और न ही निजी निवेश में वैसी तेजी दिख रही है। ऐसा लगता है मानो कॉर्पोरेट जगत के ये सैनिक मोर्चे पर जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। या तो वे जोखिम उठाने से डर रहे हैं, या फिर अपने सुरक्षित दायरे में बैठकर टैक्स छूट का मज़ा लेने में ही उन्हें ज्यादा आराम मिल रहा है।

प्रधानमंत्री की यह पीड़ा फिक्की के कार्यक्रम में दिए गए उनके भाषण में साफ सुनाई दी। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का हिसाब देते हुए याद दिलाया कि 2014 में देश में मूल कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत हुआ करती थी, जिसे उनकी सरकार ने घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया। इतना ही नहीं, आज भारत में 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों की चुटकी लेते हुए जो तंज कसा, वह उनके मन की पूरी बात कह गया। उन्होंने कहा मुझे पता है कि आप तालियां बजाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को चाहे कितना भी दे दिया जाए, आपकी भूख कभी शांत ही नहीं होती।

अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों को सीधा आईना दिखाया। उनके सटीक शब्द थे क्या आपने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई? क्या आपने नए लोगों को नौकरी पर रखा? नहीं! आपका रवैया बस यही रहता है कि मोदी जी आप करिए, हम बाद में देखेंगे। यह सीधे तौर पर कॉर्पोरेट इंडिया पर प्रधानमंत्री का एक तीखा तंज था, जिसने उद्योग जगत को सकते में डाल दिया। जहां एक तरफ इंडिया इंक (कॉर्पोरेट जगत) अपने आहत स्वाभिमान को संभालने में जुटा था, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस ने तुरंत प्रधानमंत्री के इन शब्दों को लपक लिया। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि वे तो शुरू से यही बात कह रहे थे। इस मुद्दे पर सबसे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोर्चा संभाला।

रायपुर विमानतल पर आएगा 100 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट, बनेगा पैरेलल टैक्सीवे, बढ़ेगी फ्लाइटों की संख्या

एयरपोर्ट का होगा विस्तार, 30 से 35 फ्लाइटें हो सकेंगी हैंडल

रायपुर। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल के नए निदेशक मोहम्मद आरिफ ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने बताया कि वे अमृतसर, गोवा और कोलकाता में कमर्शियल सर्विस दी है, इसके बाद दो एयरपोर्ट में निदेशक के रूप में सेवा दी है।

मोहम्मद आरिफ ने रायपुर एयरपोर्ट के विकास को लेकर सबसे बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि रायपुर में 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आने वाला है।

बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान निदेशक मोहम्मद आरिफने बताया कि इस प्रोजेक्ट में पैरेलल टैक्सीवे का निर्माण किया जाएगा, जिसमें रनवे स्पेस और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद एयरपोर्ट की क्षमता में बड़ा इजाफ होगा।



वर्तमान में रायपुर एयरपोर्ट दिन भर में 13 से 24 जहाज को हैंडल करता है, वहीं 100 करोड़ के प्रोजेक्ट और विस्तार कार्य के पूरा होने के बाद 30 से 35 फ्लाइटों को हैंडल किया जा सकेगा।

32 लाख यात्रियों की क्षमता, हर साल 5 % ग्रोथ- रायपुर विमानतल की बात करें तो वर्तमान में 32 लाख पैसेंजर की कैपेसिटी 1 साल में यह एयरपोर्ट रखता है। 2024-25 में लगभग 25 लाख पैसेंजर को हैंडल किया गया था, वहीं 2026 में लगभग 26 से 27 लाख के आसपास पैसेंजर को हैंडल किया जा रहा है, जो कि 5त्न की ग्रोथ रेट है। निदेशक ने बताया कि इंडियन डोमेस्टिक सेगमेंट मार्केट में भारत तीसरे नंबर पर मौजूद है। 2014 में भारत में 7 एयरपोर्ट थे, वहीं वर्तमान में भारत में अब 160 एयरपोर्ट हो गए हैं।

चेकिंग और पार्किंग की व्यवस्था भी मजबूत- उन्होंने बताया कि विमानतल में अलग-अलग टच प्वाइंट होते हैं। एंट्री गेट में लगभग 15 चेकिंग प्वाइंट हैं, जिसमें 1 घंटे में लगभग 900 लोगों की चेकिंग की जा सकती है। बैग चेकिंग के लिए तीन एक्स-रे थे, जिन्हें बढ़ाकर अब चार कर दिया गया है। पहले विमानतल के पास 9 पार्किंग स्टैंड थे, जिन्हें बढ़ाकर 10 से 13 किया गया है।

यात्रियों के लिए बनेगी 10 मीटर लंबी कैनोपी- उन्होंने बताया कि बारिश, धूप और यात्रियों की सुविधा देने के लिए एक कैनोपी डेवलप की जा रही है, जिसकी लंबाई लगभग 10 मीटर होने वाली है। कैनोपी की डिजाइन को री-डिजाइन किया गया है, क्योंकि दिल्ली-मुंबई में इसकी वजह से हादसे भी हो चुके हैं, जिसे लेकर हम सजग हैं।



हर बच्चे के बेहतर बचपन की सीखः गुजरात के नन्द घरों का अवलोकन करने पहुंचीं मंत्री राजवाड़े

रायपुर। हर बच्चे को पोषण, सीखने और सुरक्षित बचपन का अवसर मिले इसी संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने गुजरात प्रवास के दौरान गांधीनगर यूनिट 2 के ग्राम करई में नन्द घरों (आंगनबाड़ी) का भ्रमण किया। आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्होंने बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को देखा और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।नक्शे देखें

बच्चों की खिलखिलाहट, सीखने की जिज्ञासा और उनके बेहतर भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने केंद्रों की कार्यप्रणाली को करीब से समझा।

नन्द घर केवल सेवा केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के शुरुआती जीवन को संबल देने और माताओं तक जरूरी सहयोग पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। यहां मिलने वाली देखभाल और सीखने का वातावरण बच्चों के आत्मविश्वास और विकास की नींव मजबूत करता है। गांधीनगर स्थित सचिवालय में मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने गुजरात की महिला एवं बाल विकास (महिला एवं बाल कल्याण) मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. मनीषा राजीवभाई वकील से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सामरी की विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा,गुजरात के महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री राकेश शंकर और छत्तीसगढ़ की विभागीय संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे।

आज गांधी मैदान में संविधान रक्षा मार्च, किसान कांग्रेस के 700 कार्यकर्ता होंगे शामिल

रायपुर। रायपुर के गांधी मैदान में गुरुवार को होने वाली संविधान रक्षा मार्च एवं सम्मेलन की तैयारी को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरगुजा से लेकर बस्तर तक के सभी जिला अध्यक्षों एवं प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा की। जिसमें सभी जिला अध्यक्षों एवं प्रदेश पदाधिकारियों ने भारी संख्या में अपने साथियों के साथ कार्यक्रम में भाग लेने और संविधान की रक्षा करके देश में लोकतंत्र की बहाली करवाने में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाने का संकल्प अपने प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा के सामने लिया। उपरोक्त जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी गौरीशंकर पांडे ने बताया कि गुरुवार के संविधान मार्च कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी मनोज नचार के मार्गदर्शन एवं गरिमामयी उपस्थिति में, छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में किसान कांग्रेस के लगभग 700 पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपरोक्त कार्यक्रम में भाग लेंगे।जिसमें रायपुर शहर के निकट के जिले रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, कांकेर का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। बाकी जिलों से सभी प्रदेश पदाधिकारियों, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को उपस्थित होने का निर्देश प्रदेश अध्यक्ष ने दिया।

संविधान गौरव दिवस पर आज रायपुर में होगा आयोजन, मुख्यमंत्री होंगे मुख्य अतिथि



रायपुर। भारतीय संविधान के गौरव, मूल्यों एवं लोकतांत्रिक परम्पराओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा कल 26 नवम्बर को संविधान गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन शहीद स्मारक भवन रायपुर किया जाएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव सय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव करेंगे। आयोजन में मुख्य वक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति डॉ. गौतम भादुड़ी और भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता व सांसद संतोष पाण्डेय होंगे। विशेष अतिथि प्रदेश के विधि एवं विधायी मंत्री गजेंद्र यादव और सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर के विधायकगण राजेश मूणत, सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा व मोतीलाल साहू, महापौर श्रीमती मीनल चौबे तथा भाजपा रायपुर शहर व ग्रामीण जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर व श्याम नारंग जी (रायपुर ग्रामीण) उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम राजधानी रायपुर के रजबंधा मैदान स्थित शहीद स्मारक भवन में अपराह्न 3:30 बजे से प्रारम्भ होगा।

आज से 23 दिन तक रद्द रहेंगी 65 ट्रेनें

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने झारसुगुड़ा और चांपा में चल रहे विकास और तकनीकी कार्यों के चलते 65 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 26 नवंबर से 18 दिसंबर तक कुल 23 दिनों के लिए रेल परिचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान कई गाडियों को रद्द करने के साथ कुछ को बीच रास्ते में समाप्त किया जाएगा, जबकि कई ट्रेनें बदले हुए मार्ग और देरी से चलेंगी। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में अधोसंरचना विकास के तहत 27 नवंबर से 17 दिसंबर तक नॉन-इंटरलॉकिंग का काम होगा। इसके अलावा बिलासपुर-झारसुगुड़ा के बीच 206 किलोमीटर लंबी चौथी



रेल लाइन परियोजना में चांपा स्टेशन को जोडने और चांपा-जांजगीर नैला सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग का कार्य किया जाएगा। इसके चलते 6 से 18 दिसंबर के बीच कई गाडियां प्रभावित होंगी। वहीं, 7 से 18 दिसंबर तक कोरबा-रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस को रायपुर के बजाय केवल कोरबा-बिलासपुर के बीच पैसेंजर बनाकर चलाया जाएगा। इतवारी-टाटानगर 29 नवंबर और 1 से 16 दिसंबर तक, टाटानगर-बिलासपुर 4, 5 व 7 से 15 दिसंबर तक तथा बिलासपुर-टाटानगर 5, 6 व 8 से 16 दिसंबर तक कैंसिल रहेगी। हावड़ा-पुणे दुरंतो 26 नवंबर, 3, 7, 12, 14, 15 व 16 दिसंबर को और पुणे-हावड़ा दुरंतो 28 नवंबर, 5, 8, 14, 15, 16 व 17 दिसंबर को रद्द रहेगी। सांतरागाछी-पुणे 5 व 12 दिसंबर, पुणे-सांतरागाछी 7 व 14 दिसंबर, मालदा टाउन-सूरत 5 व 12 दिसंबर, सूरत-मालदा टाउन 7 व 14 दिसंबर, कामाख्या-एलटीटी 5 व 12 दिसंबर, एलटीटी-कामाख्या 8 व 15 दिसंबर को नहीं चलेगी। हटिया-दुर्ग 8 व 10 दिसंबर, दुर्ग-हटिया 9 व 11 दिसंबर, हटिया-पुणे 7 व 11 दिसंबर, पुणे-हटिया 9 व 13 दिसंबर, शालीमार-भुज 5 व 12 दिसंबर, भुज-शालीमार 8 व 15 दिसंबर, एलटीटी-शालीमार 9, 10 व 14 दिसंबर तथा शालीमार-एलटीटी 11, 12 व 16 दिसंबर को रद्द रहेगी।

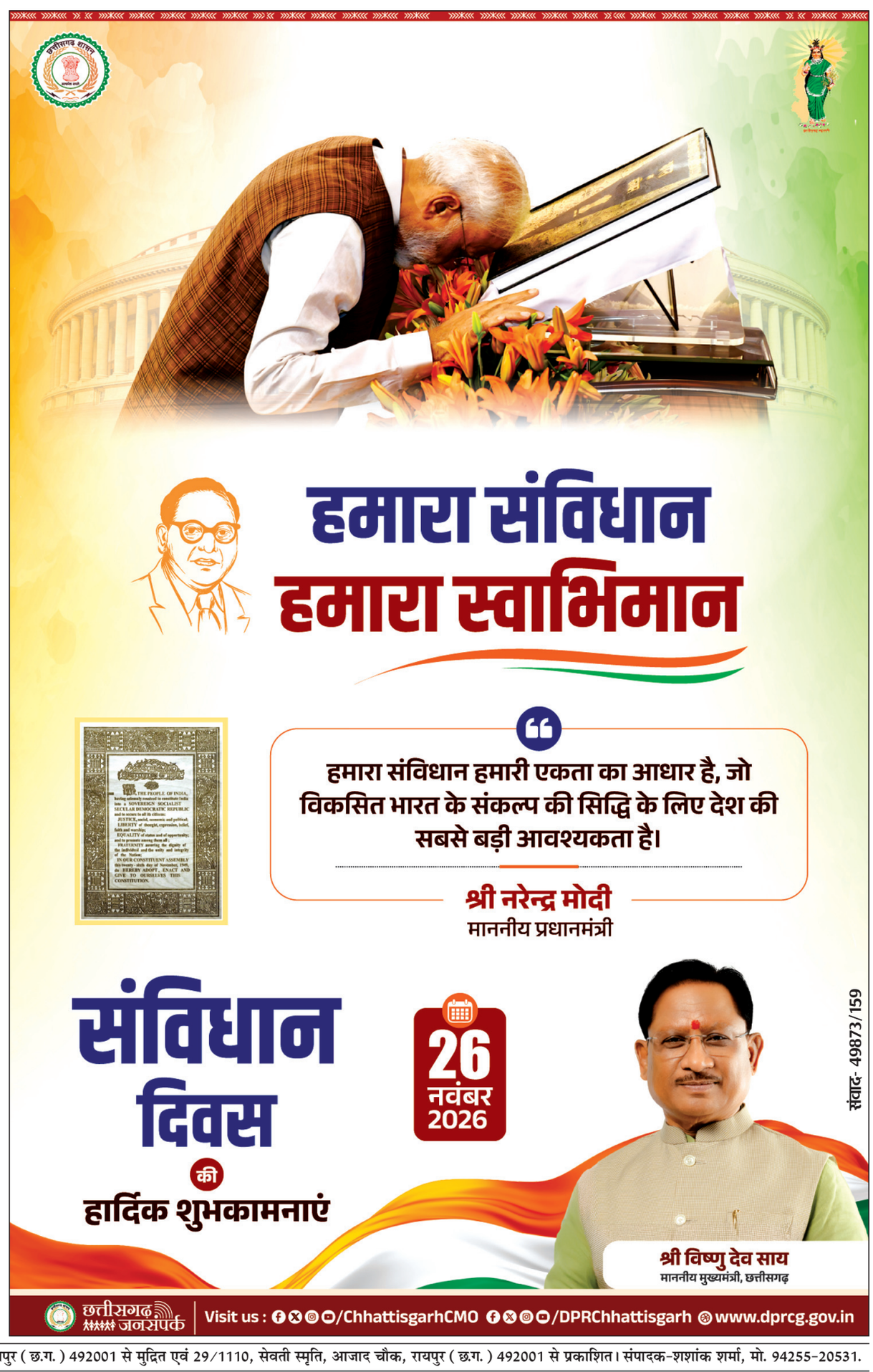
कर्म, कुंडली, वास्तु और ब्रह्मांड का संगम

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफकॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी एवं महिला चेंबर की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. ईला गुप्ता के कुशल नेतृत्व और प्रेरणादायी मार्गदर्शन में महिला चेंबर के तत्वावधान में 'स्वावलंबन से उदित-उदय (नवचेतना-नव भविष्य)' थीम के अंतर्गत मुख्य वक्ता डॉ. आशीष पाटनी का विशेष मोटिवेशनल प्रोग्राम Explore Your Energy अपनी ऊर्जा को जानो, अपना भविष्य संवारो' का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन जी.एस.एल. गर्ल्स हॉस्टल, सेमिनार हॉल, समता कॉलोनी, रायपुर में किया गया। रायपुर में डॉ. आशीष पाटनी का यह प्रथम Explore Your Energy प्रोग्राम रहा, जो पूरी तरह समाधान-केंद्रित, मंत्रमुग्ध करने वाला और ऊर्जावान साबित हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ चेंबर के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी एवं महिला चेंबर की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. ईला गुप्ता ने कहा कि व्यापारिक, शैक्षणिक और पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए तनावमुक्त और ऊर्जावान रहना बेहद जरूरी है। उपस्थित सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने उनके कुशल नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में संगठन निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है और Explore Your Energy (E.Y.E.) जैसा जीवनोपयोगी कार्यक्रम इसी सकारात्मक सोच का परिणाम है। कार्यक्रम के आयोजन स्थल एवं सहभागिता के लिए जी.एस.एल. गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका प्रियंका अग्रवाल एवं संचालक नवय अग्रवाल का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने इस आयोजन के लिए स्थान उपलब्ध कराया तथा हॉस्टल की छात्राओं की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित की।



प्रदेश में डिजिटल तकनीक से आधुनिक होगी पंजीयन व्यवस्था, 'धरोहर' पोर्टल का पायलट परीक्षण शुरू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पंजीयन सेवाओं के आधुनिकीकरण और डिजिटल रूपांतरण की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। नागरिकों को सरल, सहज, सुरक्षित एवं पारदर्शी पंजीयन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा नवीन 'धरोहर' पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल का पायलट परीक्षण रायपुर के तेलीबांधा स्थित उप पंजीयक कार्यालय क्रमांक-06 में प्रारंभ किया गया है। राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवाओं में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में पंजीयन विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए तकनीकी एवं प्रक्रियागत सुधार किए जा रहे हैं। 'धरोहर' पोर्टल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से पंजीयन प्रक्रिया में आधुनिक डिजिटल सुविधाओं का समावेश कर नागरिकों के समय और श्रम की बचत करने का प्रयास किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य नई प्रणाली का व्यावहारिक परीक्षण करना, तकनीकी चुनौतियों की पहचान करना तथा प्राप्त अनुभवों और सुझावों के आधार पर आवश्यक सुधार करना है, ताकि प्रदेश स्तर पर लागू करने से पहले पोर्टल को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जा सके। 'धरोहर' पोर्टल में अधिवक्ताओं एवं दस्तावेज लेखकों के पंजीयन और आईडी जारी करने की प्रक्रिया को सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाया गया है। रायपुर जिले में अब तक आईडी अनुमोदन के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इनमें 33 अधिवक्ताओं और 2 दस्तावेज लेखकों के आवेदन शामिल हैं।झ विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर उनका परीक्षण कर तत्काल अथवा यथाशीघ्र अनुमोदन किया जा रहा है। आईडी अनुमोदित होने के बाद संबंधित अधिवक्ता एवं दस्तावेज लेखक अपनी आईडी के माध्यम से 'धरोहर' पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले पक्षकारों के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पोर्टल पर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन, नवीनीकरण और प्रोफाइल अपडेट करने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।



सरकारी कार्यालयों, पेट्रोल पंप, बैंकों और ऑटो डीलर्स के यहां लगाए जा रहे क्यूआर कोड

ई-चालान भरना हुआ आसान, क्यूआर कोड स्कैन करते ही मिलेगी पूरी जानकारी

रायपुर। राजधानी रायपुर में अब वाहन चालकों के लिए ई-चालान की जानकारी प्राप्त करना और उसका ऑनलाइन भुगतान करना आसान हो गया है। यातायात पुलिस कमिश्नरेट ने इसके लिए त्वक्र कोड सुविधा शुरू की है। अब वाहन मालिक अपने मोबाइल फोन से त्वक्र कोड स्कैन कर अपने वाहन पर जारी ई-चालान का विवरण देख सकेंगे और ऑनलाइन भुगतान भी कर सकेंगे।

डीसीपी ट्रैफिक्र ने की नियमों के पालन की अपील- डीसीपी ट्रैफिक्र डॉ. अर्चना झा ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और अपने वाहन पर जारी ई-चालान की जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करने की अपील की है।



उन्होंने चालान का समय पर भुगतान करने और त्वक्र कोड सुविधा का लाभ उठाने का आग्रह किया है।ई-चालान की जानकारी और ऑनलाइन भुगतान के लिए आधिकारिक वेबसाइट: https://echallan.parivahan.nic.in

यातायात हेल्पलाइन: 479210632

यातायात पुलिस ने नागरिकों से सुरक्षित और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाने में सहयोग करने की अपील की है।

लंबित ई-चालान के निराकरण में मिलेगी मदद- रायपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफ्रिक कैमरों और यातायात पुलिस के माध्यम से लगातार ई-चालान जारी किए जा रहे हैं।

चालान जारी होने पर वाहन मालिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर स्त्रू के जरिए सूचना भी भेजी जाती है। इसके बावजूद जानकारी के अभाव में कई वाहन मालिक अपने चालान की स्थिति नहीं देख पाते और भुगतान लंबित रह जाता है।

सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जा रहे क्यूआर कोड- यातायात पुलिस ने इस सुविधा को अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने के लिए शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर क्यूआर कोड चस्पा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें शासकीय कार्यालय, पेट्रोल पंप, ऑटो डीलर्स, बैंक और यातायात थाने शामिल हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.